गरवी गुजरात

RNI No. GUJHIN/2011/39228

GARVI GUJARAT

गरवी गुजरात

अहमदाबाद से प्रकाशित दैनिक

वर्ष : 15
अंक : 094
दि. 02.08.2025,
शनिवार
पाना : 04
किंमत : 00.50 पैसा

EDITOR : MANOJKUMAR CHAMPAKLAL SHAH Regd. Office: TF-01, Nanakram Super Market,Ramnagar,Sabarmati, Ahmedabad-380 005. Gujarat, India.

Phone : 90163 33307 (M) 93283 33307, 98253 33307 • Email : garvigujarat2007@gmail.com • Email : garvigujarat2007@yahoo.com • Website : www.garvigujarat.co.in

प्रधानमंत्री मोदी का 51वां काशी दौरा, 52 प्रोजेक्ट करेंगे लॉन्च, किसानों को देंगे 20,500 करोड़ की सौगात

नई दिल्ली, (जीएनएस)।

देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी का दौरा करेंगे, जहां वो करीब 2,183.45 करोड़ रुपये की लागत वाली 52 विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे. रक्षाबंधन से पहले सावन के महीने में उनका यह दौरा पूर्वांचल के विकास को नई गति देगा.

जिन परियोजनाओं का पीएम शिलान्यास करेंगे उसमें सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा, खेल, पर्यटन और शहरी विकास से जुड़े कार्य शामिल हैं. इनमें सड़क चौड़ीकरण, अस्पतालों का उन्नयन, शैक्षणिक संस्थानों का विस्तार, पेयजल और सफाई योजनाएं, खेल आधारभूत ढांचे का विकास, होम्योपैथिक कॉलेज की स्थापना, धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए घाटों का निर्माण, विद्युत और पार्किंग सुविधाएं, तालाबों का पुनर्निर्माण और पुस्तकालय, पशु चिकित्सालय और डॉग केयर सेंटर शामिल हैं.

पीएम मोदी इस अवसर पर प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 20वीं किस्त भी जारी करेंगे, जिसके तहत देशभर के 9.70 करोड़ से अधिक किसानों को 20,500 करोड़ सीधे उनके बैंक खातों में हस्तांतरित किए जाएंगे. इसके साथ ही दिव्यांगजनों और वरिष्ठ नागरिकों को सहायक उपकरण वितरित किए जाएंगे.

सेवापुरी विधानसभा क्षेत्र के बनौली (कालिका धाम) गांव में विशाल जनसभा आयोजित की जाएगी,

जिसमें प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शामिल होंगे. बीजेपी का दावा है कि इस सभा में 50,000 से अधिक लोग शामिल हो सकते हैं. महिलाओं, किसानों, बुद्धिजीवियों, मीडिया और विशेष रूप से सक्षम लोगों के लिए अलग-अलग ब्लॉक बनाए गए हैं.

सुबह 10 बजे वाराणसी पहुंचेंगे पीएम मोदी

यह प्रधानमंत्री मोदी का काशी का 51वां दौरा होगा. वो सुबह 10 बजे के आसपास लाल बहादुर शास्त्री अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पहुंचेंगे और वहां से हेलिकॉप्टर से जनसभा स्थल जाएंगे. इस दौरान राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उन्हें रिसीव करेंगे. वाराणसी में इस दौरे को लेकर जबरदस्त तैयारियां की जा रही हैं. शहर भर में 1,000 से अधिक होर्डिंग्स, भाजपा के झंडे और स्वागत तोरण द्वार लगाए गए हैं.

मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल की अध्यक्षता में गांधीनगर में राज्य स्तरीय 'पीएम किसान उत्सव दिवस' का आयोजन किया जाएगा

गांधीनगर, 01 अगस्त 2025 :प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की प्रेरक उपस्थिति में उत्तर प्रदेश के वाराणसी में कल राष्ट्रीय स्तर का "प्रधानमंत्री किसान उत्सव दिवस" कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा।

इस कार्यक्रम के माध्यम से प्रधानमंत्री देश के किसानों से संवाद कर, संबोधन करेंगे और किसानों के लिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान) योजना की 20वीं किस्त जारी करेंगे।

तदनुसार, मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल की अध्यक्षता में कल 2 अगस्त को गांधीनगर में राज्य स्तरीय "प्रधानमंत्री किसान उत्सव दिवस" कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा।

जबकि, कृषि मंत्री श्री राघवजी पटेल की अध्यक्षता में राजकोट में जिला स्तरीय समारोह आयोजित किया जाएगा। राज्य और जिला स्तरीय समारोहों में, प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी लाइव प्रसारण के माध्यम से किसानों को वर्चुअल माध्यम से संबोधित करेंगे।

कृषि मंत्री श्री राघव पटेल ने इस संबंध में बताया कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के करकमलों से पीएम किसान योजना की 20वीं किस्त के तहत देशभर के 9.7 करोड़ से अधिक किसानों को 20,500 करोड़ रुपये से अधिक की सहायता राशि वितरित की जाएगी।

जिसमें से गुजरात के 52.16 लाख से अधिक किसान परिवारों को 1,118 करोड़ रुपये से अधिक की सहायता सीधे उनके बैंक खातों में जमा की जाएगी।

राज्य स्तरीय समारोह में मुख्यमंत्री के करकमलों से पीएम किसान सम्मान निधि योजना के लाभार्थियों के साथ-साथ केंद्र और राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को सहायता राशि वितरित की जाएगी और प्रगतिशील किसानों को सम्मानित किया जाएगा ।

इसके अलावा, गुजरात के हर ज़िले में "पीएम किसान उत्सव दिवस" का आयोजन किया गया है। साथ ही, राज्य की ग्राम पंचायतों और 30 कृषि विज्ञान केंद्रों पर भी इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण किया जाएगा।

राज्य भर में आयोजित होने वाले इन कार्यक्रमों में राज्य मंत्रिमंडल के सदस्यों, सांसदों और विधायकों सहित पदाधिकारियों और अधिकारियों के अलावा, 2.5 लाख से अधिक किसान उपस्थित रहेंगे।

यहां यह उल्लेखनीय है कि पीएम-किसान योजना के अंतर्गत भारत में अब तक 19 किस्तों के माध्यम से 11 करोड़ से अधिक किसान परिवारों को कुल 3.69 लाख करोड़ रुपये प्रदान किए जा चुके हैं।

जिसके अंतर्गत गुजरात के लाभार्थी किसान परिवारों को 19 किस्तों के माध्यम से अभी तक कुल 19,993 करोड़ रुपये से अधिक का भुगतान बैंक खातों में किया गया है।

श्री राज कुमार अरोड़ा ने रक्षा लेखा महानियंत्रक का पदभार ग्रहण किया

श्री राज कुमार अरोड़ा ने 01 अगस्त, 2025 को रक्षा लेखा महानियंत्रक का पदभार ग्रहण कर लिया है। वे 1990 बैच के भारतीय रक्षा लेखा सेवा अधिकारी हैं। उन्हें वित्तीय नीति, लेखांकन, लेखा परीक्षा, बजट, खरीद और कार्मिक मामलों के क्षेत्रों में काफी अनुभव है। श्री राज कुमार अरोड़ा ने यूपीएससी में अपर सचिव, रक्षा मंत्रालय के अधिग्रहण कोर में वित्त प्रबंधक (वायु) और वित्त मंत्रालय में निदेशक के रूप में सरकारी सेवा हेतु प्रतिष्ठित पद संभाले हैं। उन्होंने विभिन्न कमानों के साथ-साथ रक्षा लेखा विभाग के क्षेत्रीय कार्यालयों में एकीकृत वित्तीय सलाहकार के रूप में भी कार्य किया है।

बीएसएनएल ने स्वतंत्रता दिवस के मौके पर एक महीने के लिए मुफ्त 4जी सेवाएं देने के लिए 'फ्रीडम प्लान' पेश किया

भारत की विश्वसनीय सरकारी दूरसंचार कंपनी, भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) ने आज अपना बहुप्रतीक्षित एक सीमित अवधि का 1 रुपए वाला ऑफर, 'फ्रीडम प्लान' लॉन्च किया है, जिसमें उपभोक्ताओं को पूरे एक महीने के लिए बीएसएनएल की 4 जी मोबाइल सेवाओं का इस्तेमाल करने का मौका मिलता है। यह पहल बीएसएनएल द्वारा भारत के स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में शुरू की गई है और ये नागरिकों को भारत की स्वदेशी रूप से विकसित 4जी तकनीक का बगैर किसी शुल्क के अनुभव करने का अवसर प्रदान करती है।

बिहार में प्रारूप मतदाता सूची आज जारी कर दी गई है

चुनाव आयोग द्वारा बिहार में विशेष गहन पुनरीक्षण 2025 के पहले चरण(गणना चरण) के सफल समापन के उपरांत आज दिनांक 1 अगस्त, 2025 को प्रारूप मतदाता सूची का प्रकाशन कर दिया गया है। यह सूची ऑनलाइन पोर्टल पर उपलब्ध है, साथ ही बिहार के सभी 38 ज़ि२ ने सभी 243 विधान सभा क्षेत्रों के सभी 90,712 बूथों की प्रारूप मतदाता सूची भी सभी राजनैतिक दलों से आज 1 अगस्त को साझा कर दी गई है ।

मुख्य बिंदुः चुनाव आयोग का अतुलनीय, पारदर्शी एवं निष्पक्ष टीम वर्क की मिसालः हर गाँव, हर वार्ड, हर घर तक पहुँचने तथा प्रत्येक योग्य मतदाता का नाम मतदाता सूची में जोड़ने के प्रयासों के अंतर्गत बिहार के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी (CEO)।

केंद्रीय कृषि मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान दिल्ली में आयोजित 'मेघालय अनानास महोत्सव-2025'में शामिल हुए

(जीएनएस)।

केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण और ग्रामीण विकास मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान आज दिल्ली में आयोजित 'मेघालय अनानास महोत्सव-2025'में शामिल हुए। इस अवसर पर मेघालय के मुख्यमंत्री श्री कॉनराड के. संगमा सहित केंद्र और राज्य के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।

कार्यक्रम की शुरूआत में अनानास से संबंधित विभिन्न समझौता ज्ञापनों का आदान-प्रदान हुआ। इसके बाद केंद्रीय मंत्री ने 'कृषि क्षेत्र में मेघालय की प्रगति'से जुड़ी एक संदर्भ पुस्तिका का विमोचन किया।

इस अवसर पर संबोधित करते हुए केंद्रीय कृषि मंत्री श्री शिवराज सिंह ने कहा कि मेघालय के अनानास स्वाद और गुणवत्ता की दृष्टि से विशिष्ट हैं । मेघालय के किसान, वहां के लोग ईमानदारी से अथक प्रयास कर रहे हैं, जिसके लिए वह बधाई के पात्र हैं। चाहे फल हो, मसाले हो, हल्दी, अदरक, कॉफी, चाय, कटहल, मशरूम या अन्य विभिन्न कृषि उत्पाद, सभी की गुणवत्ता उच्च और अद्भुत है। मेघालय के अधिकतर उत्पाद जैविक हैं, जिनका प्रमोशन किया जाना चाहिए।

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि पूर्वोत्तर के उत्पादों के राज्य से बाहर और विदेशों में निर्यात के लिए केंद्र सरकार, राज्य के मुख्यमंत्री और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ मिलकर काम करेगी। इस काम में प्राइवेट सेक्टर की भूमिका भी अहम है और यह प्रसन्नता की बात है कि राज्य सरकार समझौता ज्ञापन के माध्यम से इस दिशा में बल दे रही है। आगे, श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास के लिए कटिबद्ध हैं । कृषि के साथ-साथ सभी विकास कार्यों में केंद्र सरकार द्वारा मेघालय की पूरी मदद की जाएगी।

राष्ट्रपति ने आईआईटी (आईएसएम) के दीक्षांत समारोह को संबोधित किया

(जीएनएस)।

राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने आज (01 अगस्त, 2025) झारखंड के धनबाद में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (इंडियन स्कूल ऑफ माइंस), धनबाद के 45वें दीक्षांत समारोह में भाग लिया।

राष्ट्रपति ने इस अवसर पर कहा कि आईआईटी (आईएसएम), धनबाद की लगभग 100 वर्षों की गौरवशाली विरासत है। इसकी स्थापना खनन और भूविज्ञान के क्षेत्र में प्रशिक्षित विशेषज्ञ तैयार करने के लिए की गई थी। समय के साथ, इसने अपने शैक्षणिक सीमाओं का विस्तार किया है और अब विविध क्षेत्रों में उच्च शिक्षा और अनुसंधान का एक अग्रणी केंद्र बन गया है। इस संस्थान ने प्रौद्योगिकीय विकास और नवोन्मेषण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उन्होंने प्रसन्नता जताई कि आईआईटी धनबाद ने एक ऐसा इको सिस्टम विकसित किया है जहां शिक्षा और नवोन्मेषण का उद्देश्य लोगों की आवश्यकताओं और आकांक्षाओं के अनुरूप है।

उन्होंने कहा कि देश के समग्र विकास में आईआईटी-आईएसएम की महत्वपूर्ण भूमिका है। उत्कृष्ट इंजीनियरों और शोधकताओं को तैयार करने के अतिरिक्त, इस संस्थान का उद्देश्य संवेदनशील, उद्देश्यपूर्ण और सहानुभूतिशील पेशेवर भी तैयार करना हैं। हमारे देश का भविष्य आईआईटी-आईएसएम जैसे संस्थानों की प्रतिबद्धता से आकार ले रहा है, जो अत्याधुनिक अनुसंधान और नवोन्मेषण को बढ़ावा दे रहे हैं और प्रतिभाशाली युवाओं का मार्गदर्शन कर रहे हैं।

राष्ट्रपति ने कहा कि देश और विश्व जलवायु परिवर्तन और संसाधनों की कमी से लेकर डिजिटल व्यवधान और सामाजिक असमानता तक, कई जटिल और तेजी से बदलती चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में, आईआईटी-आईएसएम जैसे संस्थान का मार्गदर्शन और भी महत्वपूर्ण है। उन्होंने आईआईटी-आईएसएम से नए और स्थायी समाधान खोजने में अग्रणी भूमिका निभाने का आग्रह किया।

राष्ट्रपति ने कहा कि भारत की सबसे बड़ी शक्ति उसका विशाल मानव संसाधन है। तकनीकी शिक्षा तक बढ़ती पहुंच और डिजिटल कौशल का प्रसार भारत को एक प्रौद्योगिकीय महाशक्ति बनने की ओर अग्रसर कर रहा है। भारत की शिक्षा प्रणाली को अधिक व्यावहारिक, नवोन्मेषण -केंद्रित और उद्योग-अनुकूल बनाने से देश के युवाओं की प्रतिभा को सही दिशा मिलेगी और वे वैश्विक स्तर पर आगे बढ़ सकेंगे।उन्होंने कहा कि वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा करने के लिए अनुसंधान एवं विकास तथा स्टार्ट-अप को बढ़ावा देने के साथ-साथ पेटेंट संस्कृति को प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है।

छात्रों में समग्र सोच विकसित करने और जटिल समस्याओं के रचनात्मक समाधान खोजने के लिए, शिक्षा में अंतःविषयक दृष्टिकोण अपनाना भी अत्यंत आवश्यक है।

राष्ट्रपति ने छात्रों को सलाह दी कि वे अपने ज्ञान को केवल व्यक्तिगत उन्नति तक सीमित न रखें, बल्कि इसे जनकल्याण का माध्यम बनाएं। उन्होंने छात्रों से आग्रह किया कि वे अपने ज्ञान का उपयोग एक अधिक सशक्त और न्यायपूर्ण भारत के निर्माण में करें - जहां प्रगति के अवसर सभी के लिए उपलब्ध हों।

उन्होंने छात्रों से कहा कि वे अपने ज्ञान का उपयोग एक हरित भारत के निर्माण में करें - जहां विकास प्रकृति की कीमत पर नहीं, बल्कि उसके साथ सामंजस्य बिठाकर हो। उन्होंने कहा कि भविष्य में वे जो भी करें, उसमें उनकी बुद्धिमत्ता के साथ-साथ उनकी सहानुभूति, उत्कृष्टता और नैतिकता भी झलकनी चाहिए।

केंद्रीय मंत्री श्री राजीव रंजन सिंह ने आईजीओटी कर्मयोगी समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की

; मिशन कर्मयोगी के तहत मत्स्य पालन क्षेत्र में डिजिटल कौशल विकास में तेजी देखी गई

(जीएनएस)।

मत्स्य पालन विभाग के लिए आईजीओटी कर्मयोगी प्लेटफॉर्म पर समीक्षा बैठक 1 अगस्त 2025 को नई दिल्ली के कृषि भवन, में केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय और पंचायती राज मंत्रालय, श्री राजीव रंजन सिंह की अध्यक्षता में आयोजित की गई। इस बैठक में मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय और पंचायती राज मंत्रालय के राज्य मंत्री, प्रो. एस.पी. सिंह बघेल, मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय और अल्पसंख्यक कार्य राज्य मंत्री, श्री जॉर्ज कुरियन, सचिव (मत्स्य पालन), डॉ. अभिलक्ष लिखी और विभाग के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया।

मत्स्य पालन और मत्स्य विकास मंत्रालय के आर्थिक सलाहकार श्री अजय श्रीवास्तव ने एक विस्तृत प्रस्तुति दी। इसमें आईजीओटी कर्मयोगी प्लेटफॉर्म से सम्बंधित उपयोगकर्ता जुड़ाव, फीडबैक और प्लेटफॉर्म एनालिटिक्स के प्रमुख पहलुओं पर प्रकाश डाला गया। मिशन कर्मयोगी के तहत प्रमुख डिजिटल लर्निंग पहल के रूप में, यह प्लेटफॉर्म देश भर में मत्स्य कर्मियों की क्षमता निर्माण और कौशल बढ़ाने में एक परिवर्तनकारी भूमिका निभा रहा है। विभाग ने मुख्यालय स्तर पर 100 प्रतिशत और अधीनस्थ कार्यालयों

में 85 प्रतिशत ऑनबोर्डिंग हासिल कर ली है। शेष लक्ष्य जल्द ही पूरा होने की उम्मीद है। केंद्रीय मंत्री ने अब तक हुई प्रगति की सराहना की और अधिकारियों को निर्देश दिया कि जल्द से जल्द पूर्ण कवरेज हासिल किया जाए।

वाइस एडमिरल सीआर प्रवीण नायर, एवीएसएम, एनएम, ने कार्मिक सेवा नियंत्रक के रूप में कार्यभार संभाला

(जीएनएस)।

वाइस एडमिरल सीआर प्रवीण नायर, एवीएसएम, एनएम ने 31 जुलाई 2025 को कार्मिक सेवा नियंत्रक (सीपीएस) के रूप में पदभार ग्रहण किया। कार्यभार ग्रहण करने पर, फ्लैग ऑफिसर ने नई दिल्ली के राष्ट्रीय युद्ध स्मारक में श्रद्धांजलि अर्पित की।

वीएडीएम सीआर प्रवीण नायर को 01 जुलाई, 1991 को भारतीय नौसेना में कमीशन किया गया था। एक सर्फेस वॉरफेयर ऑफिसर के रूप में वह संचार और इलेक्ट्रॉनिक युद्ध के विशेषज्ञ हैं। उन्होंने तीन दशकों से अधिक के अपने प्रतिष्ठित नौसैनिक करियर में कई तरह की कमान, प्रचालनगत और स्टाफ नियुक्तियां की हैं। फ्लैग ऑफिसर के विशिष्ट कार्यकाल आईएनएस कृष्णा, कोरा और मैसूर पर रहे। उन्होंने फ्लीट इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर ऑफिसर और उसके बाद पश्चिमी बेड़े के फ्लीट

कम्युनिकेशंस ऑफिसर के रूप में कार्य किया। फ्लीट कम्युनिकेशन ऑफिसर के रूप में, जुलाई 2006 में इजरायल-लेबनान युद्ध के दौरान बेरूत से भारतीय नागरिकों की गैर-संघर्षपूर्ण निकासी में उनकी भूमिका के लिए उन्हें नौसेनाध्यक्ष की प्रशंसा से सम्मानित किया गया था।

फ्लैग ऑफिसर ने मिसाइल कोर्वेट आईएनएस किर्च, गाइडेड मिसाइल विध्वंसक आईएनएस चेन्नई और विमानवाहक पोत आईएनएस विक्रमादित्य की कमान संभाली है। उनकी ऑफशोर नियुक्तियों में प्रतिष्ठित नेवल वॉर कॉलेज, गोवा में डायरेक्टिंग स्टाफ, सिग्नल स्कूल में ऑफिसर-इन-चार्ज और नौसेना मुख्यालय के कार्मिक निदेशालय में कमोडोर (कार्मिक) के पद शामिल हैं। वे तीन वर्षों से अधिक समय तक भारतीय नौसेना के प्रमुख थिंक टैंक, भारतीय नौसेना सामरिक एवं परिचालन परिषद (आईएनएसओसी) के सदस्य भी रहे हैं।

सम्पादकीय

पीएम मोदी ने भारत-पाकिस्तान संघर्ष के दौरान सीजफायर को लेकर मध्यस्थता वाले दावों को सिरे से खारिज कर

संसद में ऑपरेशन सिंदूर पर कई घंटे की लंबी बहस हुई। बहस न केवल स्वस्थ सार्थक और जीवंत रही बल्कि इसने सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों को उसके बेहतर ढंग में देश के सामने रखा। खासकर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने भारत-पाकिस्तान संघर्ष के दौरान सीजफायर को लेकर मध्यस्थता वाले दावों को सिरे से खारिज कर दिया। पीएम मोदी ने कहा कि भारत ने किसी तीसरे पक्ष की मध्यस्थता स्वीकार नहीं की और न ही करेगा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हालांकि 30 बार से ज्यादा दोहरा चुके हैं कि उन्होंने सीजफायर कराया। पीएम ने ट्रंप का नाम लिए बिना इन दावों को निराधार बताया था। पीएम मोदी के भाषण में बहुत सारे सवालों के जवाब तो मिले पर बहुत सारे सवालों के जवाब नहीं मिले। सरकार ने इसका संतोषजनक जवाब नहीं दिया कि सीजफायर क्यों रोका गया? सवाल है कि जब पाकिस्तान घुटनों पर था, तब सीजफायर किन शर्तों पर और किसके कहने पर किया गया? देश तो चाहता था कि जब भारत का पलड़ा भारी था तो हमें रुकना नहीं चाहिए था और पीओके पर कब्जा कर लेना चाहिए था पर हम अचानक रुक गए। वहीं हमने पाकिस्तान को यह भी बता दिया कि हमने केवल आतंकी ठिकानों पर हमला किया है हमने पाकिस्तानी सेना और डिपेंस सिस्टम पर हमला नहीं किया। इसका नतीजा यह हुआ कि हमारी ही जमीन पर हमारे ही विमान गिराने में पाकिस्तान सफल रहा। राज्यसभा में नेता विपक्ष और कांग्रेस अध्यक्ष ने पहलगाम हमले में सुरक्षा चूक पर सवाल उठाया जिसका कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला। खरगे ने जम्मू-कश्मीर पर उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के बयान का हवाला देते हुए सरकार पर हमला बोला। मनोज सिन्हा ने स्वीकार किया कि आतंकी हमले की वजह हमारी चूक थी। उन्होंने सवाल किया कि क्या सिन्हा का बयान किसी को बचाने के लिए था? हमले की किस-किस ने जिम्मेदारी ली? किसने इस्तीफा दिया? प्रियंका गांधी ने कहा कि पहलगाम हमले के बाद किसी देश ने पाकिस्तान की निंदा नहीं की यानि पूरी दुनिया ने भारत को पाकिस्तान की बराबरी पर रखा। सरकार ने जवाब में कहा कि पाकिस्तान के साथ सिर्प तीन देश खड़े थे और दुनिया के कई देशों ने आतंकी हमले की निंदा की। बेशक, इस पर किसी ने भी पाकिस्तान को पहलगाम हमले का दोषी नहीं माना। क्या यह हमारी विदेश नीति का पदार्फाश नहीं करती? सारी दुनिया जानती है कि भारत-पाक संघर्ष में पाकिस्तान तो महज मखौटा था। असल ताकत तो चीन की थी। हम पाकिस्तान से अकेले नहीं लड़ रहे थे, बल्कि पाक-चीन गठजोड़ से लड़ रहे थे। तमाम बहस में सरकार ने एक बार भी चीन का नाम नहीं लिया जबकि हमारी सेना ने साफ कहा कि चीन-पाकिस्तान को हथियार दे रहा है और चीन सैन्य उपकरणों के कारण ही भारत के विमान गिरे। इन पर सरकार ने एक शब्द नहीं कहा और न ही एक शब्द चीन द्वारा पाकिस्तान को दी जा रही मदद पर कहा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यूं ही नहीं दावा किया था कि भारत-पाक संघर्ष के दौरान 5 लड़ावू विमान मार गिराए गए थे, हालांकि ट्रंप ने यह स्पष्ट नहीं किया कि किस देश के कितने विमान गिराए गए। इससे पहले पाकिस्तानी भी भारत के 5 लड़ावू विमान मार गिराने का दावा कर चुके हैं। हालांकि भारत ने इसे खारिज किया है। भारत की तुलना में पाकिस्तान के साथ ज्यादा देश क्यों? भारत-पाक संघर्ष के दौरान तुर्विए, अजरबैजान और चीन ने खुलकर पाकिस्तान का समर्थन किया था, जबकि भारत के पक्ष में केवल इजरायल स्पष्ट रूप से नजर आया। यहां तक कि रूस ने भी भारत को खुलकर समर्थन नहीं किया। इस मुद्दे पर बोलते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, दुनिया में किसी भी देश ने भारत को अपनी सुरक्षा में कार्रवाई करने से रोका नहीं हैं। संयुक्त राष्ट्र में 193 देश हैं और सिर्प तीन देशों ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान के समर्थन में बयान दिया था। ब्रिक्स प्रांस, रूस और जर्मनी..

कोई भी देश का नाम ले लीजिए, दुनिया भर से भारत को समर्थन मिला। पूरी बहस में एक महत्वपूर्ण मुद्दा कपिल सिब्बल ने भी उठाया। पूर्व वेंद्रीय मंत्री व राज्यसभा सदस्य कपिल सिब्बल ने देश की रक्षा तैयारियों पर भी सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि भारत के पास पाकिस्तान से युद्ध लड़ने और उसे बर्बाद करने के लिए पर्याप्त संसाधन नहीं है।

चिकित्सा क्षेत्र में आयुष का योगदान

(जीएनएस)।

आयुष मंत्रालय (एमओए) ने एक सुस्थापित संस्थागत ढांचे के माध्यम से निवारक, प्रोत्साहक और उपचारात्मक स्वास्थ्य सेवा में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। शिक्षा और पेशेवर अभ्यास का विनियमन दो वैधानिक आयोगों, आयुर्वेद, सिद्ध, यूनानी और सोवा-रिग्पा हेतु "भारतीय चिकित्सा पद्धति के लिए राष्ट्रीय आयोग" और "होम्योपैथी के लिए राष्ट्रीय आयोग" के माध्यम से नियंत्रित किया जाता है। इसके अलावा, आयुष मंत्रालय ने 12 राष्ट्रीय स्तर के शिक्षण संस्थानों की स्थापना की है जिन्होंने गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, नैदानिक सेवाओं और आउटरीच को एकीकृत करके चिकित्सा क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। वे विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रमों के साथ स्नातक, स्नातकोत्तर और डॉक्टरेट पाठ्यक्रम प्रदान करते हैं। वे एनएबीएच/ एनएबीएल (अस्पतालों और स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं के लिए राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड/ परीक्षण और अंशांकन प्रयोगशालाओं के लिए राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड) मान्यता प्राप्त अस्पतालों के माध्यम से ओपीडी/ आईपीडी (बा' रोगी विभाग/अंतरोगी विभाग) सेवाएं प्रदान करते हैं और देश भर में स्वास्थ्य शिविर, जागरूकता अभियान और समुदाय-आधारित पहल का आयोजन करते हैं।

आयुष प्रणालियों के वैज्ञानिक सत्यापन और विकास को पांच स्वायत्त अनुसंधान परिषदों द्वारा समर्थन दिया जाता है, अर्थात केंद्रीय आयुर्वेदिक विज्ञान अनुसंधान परिषद (सीसीआरएएस), केंद्रीय होम्योपैथी अनुसंधान परिषद (सीसीआरएच), केंद्रीय यूनानी चिकित्सा अनुसंधान परिषद (सीसीआरयूएम), केंद्रीय सिद्ध अनुसंधान परिषद (सीसीआरएस), और केंद्रीय योग और प्राकृतिक चिकित्सा अनुसंधान परिषद (सीसीआरवाईएन)

सीसीआरएएस, सीसीआरयूएम और सीसीआरएच अपने व्यापक नेटवर्क के माध्यम से ओपीडी और आईपीडी सेवाएँ प्रदान करते हैं और आउटरीच कार्यक्रम चलाते हैं - सीसीआरएएस के अंतर्गत 30 संस्थान, सीसीआरयूएम के अंतर्गत 21 संस्थान और सीसीआरएच के अंतर्गत 6 उपचार केंद्रों वाली 27 इकाइयाँ। इन पहलों में अनुसूचित जाति उप योजना, जनजातीय स्वास्थ्य सेवा, स्कूल स्वास्थ्य कार्यक्रम और मोबाइल नैदानिक अनुसंधान शामिल हैं, जो देश भर में आयुष स्वास्थ्य सेवा की पहुँच और सुगमता को उल्लेखनीय रूप से बढ़ाते हैं। इसके अतिरिक्त, सीसीआरएस 9 परिधीय संस्थानों के माध्यम से स्वास्थ्य सेवा प्रदान करता है, जबकि सीसीआरवाईएन 8 संस्थानों, 10 वेलनेस केंद्रों और 10 माइंड-बॉडी इंटरवेंशन केंद्रों का संचालन करता है, जो देश भर में समग्र स्वास्थ्य सेवाओं को बढ़ावा देते हैं।

आयुष गुणवत्ता-आश्वस्त आयुष औषधियों के निर्माण के लिए एक सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम इंडियन मेडिसिन्स फार्मास्युटिकल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (आईएमपीसीएल) का भी प्रबंधन करता है और एक अधीनस्थ कार्यालय, भारतीय चिकित्सा और होम्योपैथी के लिए फामाकोपिया आयोग, जो औषधि मानकीकरण के लिए जिम्मेदार है और एक केंद्रीय शीर्ष प्रयोगशाला के रूप में भी कार्य करता है।

आयुष मंत्रालय राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र सरकारों के माध्यम से राष्ट्रीय आयुष मिशन (एनएएम) की एक केन्द्र प्रायोजित योजना को भी क्रियान्वित कर रहा है और उनके द्वारा प्रस्तुत राज्य वार्षिक कार्य योजनाओं (एसएएपी) के विरुद्ध एनएएम दिशानिदेशों के प्रावधान के अनुसार विभिन्न गतिविधियों के तहत उन्हें वित्तीय सहायता प्रदान करके देश में आयुष उपचार सुविधा प्रदान करने के उनके प्रयासों का समर्थन कर रहा है।

एएसयूएंडएच (आयुर्वेद, सिद्ध, यूनानी और होम्योपैथी) औषधियों से संबंधित मामले औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 और उसके अंतर्गत बनाए गए नियम, 1945 के अंतर्गत शासित होते हैं।

आयुष मंत्रालय ने आयुर्वेद और अन्य पारंपरिक चिकित्सा प्रणालियों में चिकित्सा मूल्य यात्रा को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय के अंतर्गत भारत पर्यटन विकास निगम (आईटीडीसी) के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। आयुष मंत्रालय ने चिकित्सा मूल्य यात्रा में भारत की स्थिति को मजबूत करने के उद्देश्य से देश के पश्चिमी और दक्षिणी क्षेत्र के लिए चिकित्सा मूल्य यात्रा शिखर सम्मेलन का भी आयोजन किया। इस शिखर सम्मेलन ने आयुष- आधारित चिकित्सा मूल्य यात्रा के विस्तार के लिए राज्य सरकारों, उद्योग जगत के दिग्गजों और स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं के बीच सहयोग को बढ़ावा दिया।

सरकार ने आयुष चिकित्सा पद्धति के तहत उपचार प्राप्त करने के लिए भारत आने वाले विदेशियों और उनके परिचारकों (पाकिस्तानी नागरिक को छोड़कर) के लिए 27 जुलाई, 2023 को आयुष वीजा की एक अलग श्रेणी शुरू की है।

गृह मंत्रालय द्वारा संचालित मेडिकल और आयुष वीजा पोर्टल, वैध विदेशी मरीजों के प्रवेश को सुव्यवस्थित और विनियमित करने के लिए तैयार किया गया है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि केवल अधिकृत अस्पताल ही पूर्व- मान्य मेडिकल वीजा के माध्यम से वास्तविक मरीजों को इलाज के लिए आमंत्रित करें। यह पोर्टल पंजीकृत अस्पतालों/वेलनेस केंद्रों को मेडिकल वीजा, मेडिकल अटेंडेंट वीजा और आयुष अटेंडेंट वीजा के लिए मेडिकल वीजा आमंत्रण पत्र और विस्तार पत्र बनाने की अनुमति देता है। भारत में संचालित अस्पताल/ वेलनेस केंद्र इस पोर्टल पर पंजीकरण कर सकते हैं और गृह मंत्रालय द्वारा प्रदान किए गए लॉगिन आईडी और पासवर्ड का उपयोग करके लॉग इन कर सकते हैं। इस पोर्टल को निम्नलिखित यू आर एल पर के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है:

आयुष मंत्रालय, संरचित क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से आयुष क्षेत्र में कुशल कार्यबल को सुदृढ़ और प्रशिक्षित करने के साथ-साथ घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आयुष सेवाओं की बढ़ती आवश्यकता को पूरा करने के लिए कई पहल कर रहा है। इन पहलों का विवरण अनुलग्नक क में संलग्न है।

अनुलग्नक क

आयुष क्षेत्र के लिए कुशल कार्यबल को प्रशिक्षित करने के लिए आयुष मंत्रालय द्वारा की गई पहलों और घरेलू एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आयुष सेवाओं की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए उठाए जा रहे कदमों का विवरण:

क. आयुष मंत्रालय ने 2021-22 से 'आयुर्ज्ञान' नामक एक केंद्रीय क्षेत्र योजना लागू की है, जिसमें आयुष में क्षमता निर्माण और सतत चिकित्सा शिक्षा पर एक प्रमुख घटक शामिल है। इस घटक के अंतर्गत, देश भर के पात्र संगठनों को प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण कार्यक्रम संचालित करने हेतु सहायता प्रदान की जाती है, जिसका उद्देश्य आयुष कर्मियों को आवश्यकता-आधारित व्यावसायिक प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित करना और नैदानिक एवं तकनीकी क्षेत्रों में ज्ञान के अंतराल को पाटना है।

ख. आयुष मंत्रालय ने आयुष के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग संवर्धन हेतु केंद्रीय क्षेत्र योजना (आईसी योजना) विकसित की है। इस योजना के अंतर्गत, मंत्रालय भारतीय आयुष औषधि निमार्ताओं/ आयुष सेवा प्रदाताओं को आयुष उत्पादों और सेवाओं के निर्यात को बढ़ावा देने हेतु सहायता प्रदान करता है। यह योजना आयुष चिकित्सा पद्धतियों के अंतर्राष्ट्रीय प्रचार, विकास और मान्यता को सुगम बनाती है; हितधारकों के बीच संवाद को बढ़ावा देती है; और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आयुष के बाजार विकास को बढ़ावा देती है। इसके अतिरिक्त, यह योजना विदेशों में आयुष अकादमिक पीठों की स्थापना और प्रशिक्षण कार्यशालाओं/ संगोष्ठियों के आयोजन के माध्यम से शिक्षा और अनुसंधान को बढ़ावा देती है, जिसका उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आयुष चिकित्सा पद्धतियों के प्रति जागरूकता और रुचि को बढ़ाना है।

ग. सीसीआरएएस विभिन्न पहलों के माध्यम से आयुष अनुसंधान के क्षेत्र में क्षमता निर्माण में सक्रिय रूप से योगदान दे रहा है, जैसेः -

स्नातक आयुर्वेद छात्रों के बीच अनुसंधान योग्यता को बढ़ावा देने के लिए स्पार्क (आयुर्वेद अनुसंधान केन के लिए छात्र कार्यक्रम);

पीजी स्टार (स्नातकोत्तर विद्वानों के लिए आयुर्वेद अनुसंधान में प्रशिक्षण योजना) का मुख्य उद्देश्य स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में अध्ययनरत आयुर्वेद छात्रों में अच्छी गुणवत्ता वाले अनुसंधान को बढ़ावा देना और साथ ही बड़े शोध के लिए उनके शोध कार्य की दृश्यता और पहुंच में सुधार करना है।

उन्नत शैक्षणिक अनुसंधान का समर्थन करने के लिए पीएचडी और पोस्ट-डॉक्टरल फेलोशिप कार्यक्रम;

प्रयत्न का उद्देश्य आयुर्वेद के क्षेत्र में स्नातकोत्तर (पीजी) और डॉक्टरेट (पीएचडी) विद्वानों के बीच वैज्ञानिक लेखन कौशल को विकसित करना और बढ़ाना है;

एआरएमएस (आयुर्वेद अनुसंधान पद्धति और सांख्यिकी) प्रशिक्षण, जिसका उद्देश्य आयुर्वेद विद्वानों के लिए अनुसंधान पद्धति और बायोस्टैटिक्स में आधार तैयार करना है।

घ. आयुष चिकित्सकों की क्षमता बढ़ाने के लिए, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय (डीजीएचएस) के तहत आयुष वर्टिकल ने 13-17 मई 2024 के दौरान सभी राज्यों/ केंद्र शासित प्रदेशों के लिए मानक उपचार दिशानिदेशों (एसटीजी) पर केंद्रीय स्वास्थ्य शिक्षा ब्यूरो (सीएचईबी), डीजीएचएस के सहयोग से राष्ट्रीय स्तर पर मास्टर प्रशिक्षण आयोजित किया है, ताकि सभी उपयोगकताओं तक उनका प्रभावी प्रसार सुनिश्चित किया जा सके।

ङ. आयुष मंत्रालय की ओर से भारतीय औषधि एवं होम्योपैथी के लिए फामाकोपिया आयोग (पीसीआईएमएंडएच) औषधि नियामक प्राधिकरणों, राज्य औषधि परीक्षण प्रयोगशालाओं (औषधि विश्लेषकों) आदि को एएसयूएंडएच (आयुर्वेद, सिद्ध, यूनानी और होम्योपैथी) औषधियों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक प्रयोगशाला तकनीकों और विधियों पर प्रशिक्षण प्रदान कर रहा है।

च. इसके अलावा, विभिन्न क्षेत्रों में आयुष पेशेवरों के ज्ञान और कौशल को उन्नत करने के लिए विभिन्न राष्ट्रीय आयुष संस्थानों और अनुसंधान परिषदों में नियमित प्रशिक्षण कार्यक्रम, कार्यशालाएं और सेमिनार आयोजित किए जाते हैं।

यह जानकारी केंद्रीय आयुष राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री प्रतापराव जाधव ने आज लोकसभा में एक लिखित उत्तर में दी।

इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक (आईपीपीबी) ने निर्बाध और समावेशी डिजिटल बैंकिंग के लिए आधार के माध्यम से पहचान प्रमाणन की शुरूआत की

(जीएनएस)।

इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक (आईपीपीबी) ने ग्राहक लेनदेन के लिए आधार के माध्यम से पहचान प्रमाणन सुविधा की राष्ट्रव्यापी शुरूआत की घोषणा की है - यह एक सफल पहल है। इसका उद्देश्य बैंकिंग को अधिक सुरक्षित, समावेशी और सुविधाजनक बनाकर प्रत्येक नागरिक, विशेषकर वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांगों को सशक्त बनाना है।

यूआईडीएआई (भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण) के ढांचे के अंतर्गत विकसित फेस ऑथेंटिकेशन सुविधा ग्राहकों को बैंकिंग लेनदेन में सक्षम बनाती है, जिससे फिंगरप्रिंट या ओटीपी जैसे बायोमेट्रिक इनपुट की आवश्यकता समाप्त हो जाती है। इसके साथ, आईपीपीबी बैंकिंग को अधिक सुलभ, समावेशी और ग्राहक-केंद्रित बनाकर "आपका बैंक, आपके द्वार" के अपने मिशन को सार्थक बनाता है।

इस अवसर पर आईपीपीबी के एमडी और सीईओ, श्री आर विश्वेश्वरन ने कहा, "आईपीपीबी में हमारा मानना है कि बैंकिंग न केवल सुलभ होनी चाहिए, बल्कि सम्मानजनक भी होनी चाहिए। आधार-आधारित फेस ऑथेंटिकेशन के साथ, हम यह सुनिश्चित कर रहे हैं कि बायोमेट्रिक फिंगरप्रिंट या ओटीपी सत्यापन की सीमाओं के कारण कोई भी ग्राहक सुविधाओं का लाभ लेने से वंचित न रह जाए। यह केवल एक तकनीकी विशेषता नहीं है; यह बड़े पैमाने पर वित्तीय समावेशन को पुनर्परिभाषित करने की दिशा में एक कदम है।"

आईपीपीबी की फेस ऑथेंटिकेशन सुविधा के मुख्य लाभः

वरिष्ठ नागरिकों, दिव्यांगों और उंगलियों के निशान मिट जाने वाले व्यक्तियों के लिए समावेशी बैंकिंग।

ओटीपी या फिंगरप्रिंट सेंसर पर निर्भरता के बिना सुरक्षित आधार प्रमाणीकरण।

ग्राहकों की सुगमता के लिए तीव्र और संपर्क रहित लेनदेन।

जोखिमपूर्ण स्वास्थ्य संबंधी स्थितियों के दौरान सुरक्षित बैंकिंग।

खाता खोलना, शेष राशि की जांच, निधि अंतरण और उपयोगिता भुगतान सहित सभी बैंकिंग सेवाओं के लिए उपयुक्त।

आईपीपीबी फेस ऑथेंटिकेशन सुविधा का शुभारंभ भारत सरकार के डिजिटल इंडिया और वित्तीय समावेशन मिशन के अनुरूप है। यह सुविधा तकनीक का उपयोग करके समानता, पहुंच और सशक्तिकरण के मूल्यों को बनाए रखने के लिए मानक स्थापित करती है।

आईपीपीबी अपने सभी ग्राहकों को विशेषकर उन ग्राहकों को जिन्हें फिंगरप्रिंट-आधारित प्रमाणीकरण में चुनौतियों का सामना करना पड़ा है, इस नई सुविधा की सरलता का अनुभव करने के लिए प्रोत्साहित करता है।

इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक के बारे में

इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक (आईपीपीबी) की स्थापना डाक विभाग, संचार मंत्रालय के अंतर्गत भारत सरकार की शत-प्रतिशत प्रतिभूति के साथ की गई है।

शहनाज हुसैन के सौन्दर्य टिप्स

अपनी त्वचा की देखभाल करने के लिए आपके पास एक स्किनकेयर रूटीन होना चाहिए जो स्वयं की देखभाल करने में सक्षम हो।यह आवश्यक है कि आप सीटीएम या क्लींजिंग, टोनिंग और मॉइस्चराइजिंग जैसी बुनियादी चीजों से शुरूआत करें।याद रखें कि आपको सबसे पहले अपनी त्वचा को उन उत्पादों को सक्षम बनाने के लिए तैयार करना होगा जिन्हें आप उपयोग करने जा रहे हैं।

● एक सौम्य फेसवॉश से अपनी त्वचा को साफ करने से शुरू करें

● फिर मृत त्वचा कोशिकाओं को हटाने के लिए अपनी त्वचा को एक्सफोलिएट या स्क्रब करें

● अब एक स्किन टोनर का उपयोग करें जो त्वचा को कसने में मदद करेगा

● और तीसरे चरण में आपकी त्वचा को मॉइस्चराइज करने की आवश्यकता होती है।

● इस स्किन केयर रूटीन का पालन करें और अपनी त्वचा पर सप्ताह में दो बार स्क्रब का उपयोग करना याद रखें, आप ताजा और चमकती त्वचा के साथ अंतर देखेंगे।

2. ---------- प्रत्येक मौसम के लिए विशिष्ट स्किनकेयर रूटीन की आवश्यकता होती है, इस कारण से पर्यावरण और मौसम की स्थिति में बदलाव के साथ अपनी स्किन केयर रूटीन को बदलना महत्वपूर्ण है।

उदाहरण के लिए,

● जब मौसम शुष्क हो तो आप को पानी, ताजे फलों के रस और हाइड्रेटिंग मॉइस्चराइजर और क्रीम या स्किन सीरम पीकर अपनी त्वचा को हाइड्रेट रखना चाहिए।

● नमी वाले महीनों के दौरान, आपको हल्का मेकअप, मैटिफाइंग मॉइस्चराइजर का उपयोग करना चाहिए और सप्ताह में दो बार अपनी त्वचा को स्क्रब करना चाहिए।पूरे दिन अपनी त्वचा को तरोताजा रखने के लिए ब्लॉटिंग पेपर या स्किन वाइप्स का इस्तेमाल करें।

● आपको मौसम की स्थिति की परवाह किए बिना हर दिन सनस्क्रीन का उपयोग करना याद रखना चाहिएक्यों कि आपको अपनी त्वचा को टैनिंग, समय से पहले बूढ़ा होने और सनबर्न से बचाना चाहिए, यूवी किरणें आपकी त्वचा के लिए हानिकारक हैं इसलिए मैं इसे पूरेसाल अपने चेहरे और खुली त्वचा पर लगाने की सलाह देती हूँ।

3 ------ त्वचा की देखभाल की दिनचर्या के लिए आपको 10 वर्ष की आयु से ही शुरूआत कर देनी चाहिए, क्योंकि जितनी जल्दी आप शुरूआत करेंगे, आपकी त्वचा के लिए उतने ही अच्छे परिणाम मिलेंगे।हालाँकि , यदि आप जानना चाहते हैं कि किस उम्र में सौंदर्य प्रसाधन या मेक अप का उपयोग शुरू करना चाहिए, तो मेरा सुझाव है कि 14 वर्ष की आयु से पहले ऐसा न करें।मेरी सलाह है कि अपनी त्वचा पर मेकअप या रासायनिक सौंदर्य प्रसाधनों का उपयोग करने के बजाय, आयुर्वेदिक त्वचा देखभाल उत्पादों का उपयोग करें जो आपकी त्वचा की गुणवत्ता को बढ़ाएंगे।

4. ------40 की उम्र के बाद आपकी त्वचा को भरपूर मात्रा में नमी की जरूरत होती है क्योंकि यह वह उम्र है जब आपकी त्वचा अपनी नमी तेजी से खो देतीहै।मेरा सुझाव है किः

● त्वचा को नमी देने वाले सीरम , हाइड्रेटिंग क्लींजर, हाइड्रेटिंग मॉइस्चराइजर का इस्तेमाल करना शुरू करें।

● अपनी त्वचा को सप्ताह में तीन बार हर दूसरे दिन हल्के एक्सफोलीएटिंग साफ करना न भूलें ताकि आपकी त्वचा की कोशिकाएं फिर से जीवित हो जाएँ और आप तरोताजा दिखें।

● इसके अलावा, अपनी त्वचा को सूरज की किरणों से होने वाले नुकसान से बचाने के लिए रोजाना सनस्क्रीन का इस्तेमाल करें।

आपकी रात की दिनचर्या में मेकअप हटाना, त्वचा साफ करना, त्वचा को एक्सफोलिएट करना, फिर स्किन सीरम, नाइट क्रीम लगाना और अपनी आँखों के नीचे जेल लगाना शामिल होना चाहिए। 40 के बाद आपकी आँखों के नीचे की त्वचा को स्वस्थ रखने के लिए विशेष देखभाल की जरूरत होती है।

5. उम्र बढ़ने पर महिलाओं को त्वचा की देखभाल करने के लिए सौंदर्य प्रसाधनों के प्रयोग के इलावा क्या करना चाहिए ?

40 के बाद एक स्वस्थ जीवन शैली अपनाना बहुत जरूरी है जो आपकी त्वचा की देखभाल के लिए सहायक हो, क्योंकि एक के बिना दूसरे का कोई मतलब नहीं रहजाता।

ङ्ग मैं तनाव मुक्त जीवन जीने का सुझाव देती हूँ, ध्यान, माइंडफुलनेस और योग जरूरी है।मौसमी फलों और सब्जियों का रोजाना सेवन करने जैसी स्वस्थ खाने की आदतें अपनाएँ।

ङ्ग एंटीऑक्सीडेंट युक्त खाद्य पदार्थों को शामिल करें जो त्वचा के अच्छे स्वास्थ्य को बनाए रखने में मदद करेंगे जैसे कि बेरीज, पालक, सेब, अंगूर।

ङ्ग अखरोट, सूरजमुखी के बीज, बादाम और तिल जैसे मेवे औरबीज।

ङ्ग कैफीन युक्त पेय और शराब से बचें, इसके बजाय बिना चीनी वाली ग्रीन टी पिएँ।

ङ्ग पर्याप्त आराम करें, मतलब है कि आपकी त्वचा और स्वास्थ्य को फिर से जीवित करने के लिए 8 घंटे की नींद जरूरी है।

ङ्ग अगर आप धूम्रपान करते हैं तो धूम्रपान छोड़ दें क्योंकि यह त्वचा के कोलेजन को नुकसान पहुँचाताहै।

6.

आपकी त्वचा को सुंदर और स्वस्थ रहने के लिए बहुत अधिक देखभाल की आवश्यकता होती है इसलिए ऐसी जीवनशैली अपनाना आवश्यक है जो त्वचा के स्वास्थ्य का समर्थन करती हो।इसमें एक समर्पित स्किन केयर रूटीन शामिल हैः

● अपनी त्वचा की जरूरतों को नजरअंदाज न करें उदाहरण के लिए शुष्क त्वचा को हाइड्रेशन की आवश्यकता होती है, तैलीय त्वचा को मैटिफाइंग उत्पादों का उपयोग करने की आवश्यकता होती है/ संवेदनशील त्वचा को ऐसे उत्पादों की आवश्यकता होती है जो कठोर रसायनों से मुक्त हों, जैसे आयुर्वेद आधारित स्किन केयर उत्पाद।

● याद रखें कि आप जो खाते हैं उसका आपकी त्वचा के स्वास्थ्य पर बहुत प्रभाव पड़ता है और आपअपनी त्वचा पर क्या लगाते हैं उसका भी यही असर होता है।समझदारी से चुनें कि आप अपनी त्वचा पर क्या लगाते हैं और क्या खाते हैं, चीनी युक्त भोजन और पेय आपकी त्वचा को नुकसान पहुँचाते हैं।

● बहुत अधिक तैलीय भोजन आपकी त्वचा और आंत के लिए हानिकारक है।

● आपकी आंत का स्वास्थ्य भी आवश्यक है इसलिए मैं आपके आहार में दही को शामिल करने का सुझाव देती हु।

लेखिका अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त सौन्दर्य विशेष्ज्ञ है और हर्बल क्वीन के रूप में लोक प्रिय हैं

निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण निधि प्राधिकरण (आईईपीएफए) एकीकृत पोर्टल लॉन्च करने की तैयारी

(जीएनएस)।

निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण निधि प्राधिकरण (आईईपीएफए) अपने एकीकृत पोर्टल के परीक्षण के अंतिम चरण में है। यह एक एकीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म है, जिसे दावा प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करने और निवेशकों व कंपनियों, दोनों के लिए पहुँच बढ़ाने के लिए डिजाइन किया गया है। यह पोर्टल प्रमुख हितधारकों, जिसमें डिपॉजिटरी और सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (पीएफएमएस) शामिल हैं, उन्हें एकीकृत करेगा, ताकि एक सहज और कुशल अनुभव प्रदान किया जा सके।

कंपनियों द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों की सटीकता सुनिश्चित करने और दावा प्रक्रिया को सुचारू रूप से चलाने के लिए, नियम 1(ए) के तहत सार्वजनिक नोटिस, आधिकारिक आईईपीएफए वेबसाइट पर उपलब्ध हैं। इन नोटिसों में उन कंपनियों से आग्रह किया गया है, जिन्होंने अभी तक अपने आईईपीएफ-1/7 एसआरएन और निर्धारित एक्सेल टेम्पलेट अपलोड नहीं किए हैं, कि वे इस प्रक्रिया को जल्द से जल्द पूरी करें। निर्बाध दावा प्रक्रिया के लिए समय पर अनुपालन जरुरी है।

इसके साथ ही, आईईपीएफए, एक सरल और दावों को तेजी से निपटाने की प्रक्रिया शुरू करने के लिए, कम मूल्य के दावों हेतु दस्तावेजीकरण की जरुरतों की व्यापक समीक्षा कर रहा है। इसके अलावा, अपनी शिकायत निवारण प्रणाली को मजबूत करने के लिए, आईईपीएफए एक एकीकृत कॉल सेंटर भी शुरू कर रहा है, जो अधिक कुशल, उत्तरदायी और हितधारकों के अनुकूल संचार व्यवस्था प्रदान करेगा।

इन तकनीकी और प्रक्रियात्मक अपग्रेड के दौरान, कुछ छोटे अस्थायी व्यवधान भी उत्पन्न हो सकते हैं। आईईपीएफए किसी भी असुविधा के लिए खेद व्यक्त करता है और एक अधिक मजबूत और निवेशक-केंद्रित व्यवस्था के निर्माण की दिशा में हितधारकों के निरंतर सहयोग की उम्मीद करता है।

आईईपीएफए के बारे में

भारत सरकार के कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय के अधीन कार्यरत, निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण निधि प्राधिकरण (आईईपीएफए), बिना दावे वाले शेयरों और लाभांशों की वापसी की सुविधा प्रदान करके और देश भर में वित्तीय साक्षरता को बढ़ावा देकर निवेशकों के हितों की रक्षा के लिए समर्पित है। निवेशक दीदी, निवेशक पंचायत और निवेशक शिविर जैसी प्रमुख पहलों के जरिए, आईईपीएफए लोगों को सूचित वित्तीय फैसले लेने में सक्षम बनाता है और वित्तीय रूप से जागरूक नागरिकों को प्रेरित करता है।

RNI No. GUJGUJ/2011/39228 Published & Owned by AJAYKUMAR RAMANLAL PRAJAPATI and Printed By (1) JIGNESH RASHIKBHAI GAJJAR at Vansh Corporation, A/8, Shayona Golden Estate, Shahibag, Ahmedabad - 380 004, Ahmedabad,Gujarat-380 004. (2) DESAI RAHUL MAHESHBHAI at Bhavani Offset,Bhatiya Ni Wadi, Opp Railway Station, Kalupur, Ahmedabad,-380002,Ahmedabad,Gujarat-380 002 (3) HARDIK MAHESHBHAI DESAI at Bhoomi Offset,Bhatiya Ni Wadi, Opp Railway Station, Kalupur, Ahmedabad,-380002,Ahmedabad,Gujarat-380 002. and Published from TF-01, Nanakram Super Market, Ramnagar, Sabarmati, Ahmedabad - 380 005. Editor : MANOJKUMAR CHAMPKLAL SHAH

11 अगस्त से भावनगर टर्मिनस से अयोध्या कैंट के बीच साप्ताहिक एक्सप्रेस ट्रेन का संचालन

माननीय रेल मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव जी 03 अगस्त, 2025 को भावनगर टर्मिनस से भावनगर टर्मिनस-अयोध्या केंट एक्सप्रेस तथा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से रीवा-पुणे (हड़पसर) और जबलपुर-रायपुर एक्सप्रेस उद्घाटक ट्रेनों का हरी झंडी दिखाकर शुभारंभ करेंगे।

यात्रियों की मांग एवं उनकी सुविधा को ध्यान में रखते हुए रेल प्रशासन द्वारा पश्चिम रेलवे के भावनगर टर्मिनस स्टेशन से भगवान श्री राम की नगरी अयोध्या के लिए 11 अगस्त, 2025 से प्रति सोमवार भावनगर टर्मिनस और अयोध्या कैंट के बीच साप्ताहिक एक्सप्रेस ट्रेन चलाने का निर्णय लिया गया है। भावनगर-अयोध्या केंट एक्सप्रेस ट्रेन का विस्तृत विवरण निम्नानुसार हैः-

ट्रेन नंबर 19201/19202 भावनगर-अयोध्या कैंट-भावनगर साप्ताहिक एक्सप्रेस

ट्रेन नंबर 19201 भावनगर टर्मिनस-अयोध्या कैंट साप्ताहिक एक्सप्रेस ट्रेन 11 अगस्त, 2025 (सोमवार) को भावनगर टर्मिनस से दोपहर 13.50 बजे प्रस्थान करेगी और अगले दिन 18.30 बजे अयोध्या कैंट स्टेशन पहुंचेगी। इसी प्रकार वापसी में, ट्रेन नंबर 19202 अयोध्या कैंट-भावनगर साप्ताहिक एक्सप्रेस ट्रेन 12 अगस्त, 2025 (मंगलवार) को अयोध्या कैंट स्टेशन से रात्रि 22.30 बजे प्रस्थान करेगी और गुरूवार को प्रातः 04.45 बजे भावनगर टर्मिनस पहुंचेगी।

यह ट्रेन दोनों दिशाओं में भावनगर परा, सिहोर, धोला, बोटाद, लींबडी, सुरेन्द्रनगर गेट, विरमगाम, महेसाना, पालनपुर जंक्शन, आबूरोड, फालना, मारवाड़ जंक्शन, ब्यावर, अजमेर जंक्शन, किशनगढ़, जयपुर जंक्शन, गांधीनगर जयपुर, बाँदीकुई जंक्शन, भरतपुर जंक्शन, ईदगाह, टूण्डला जंक्शन, कानपुर सेंट्रल, लखनऊ एवं बाराबंकी जंक्शन स्टेशनों पर रूकेगी। इस ट्रेन में द्वितीय श्रेणी, शयनयान, थर्ड एसी, थर्ड एसी इकोनॉमी एवं सेकंड एसी के कोच होंगे।

ट्रेन नंबर 19201 की बुकिंग 03.08.2025 से यात्री आरक्षण केन्द्रों और आईआरसीटीसी की वेबसाइट पर शुरू होगी। इस ट्रेन के ठहराव, संरचना और समय के बारे में विस्तृत जानकारी के लिए यात्री कृपया वेबसाइट www. enquiry. indianrail. gov.in पर जाकर अवलोकन कर सकते हैं।

अहमदाबाद मंडल के लोकोमोटिव शेड, साबरमती में मॉक ड्रिल का आयोजन

पश्चिम रेलवे के अहमदाबाद मंडल पर लोकोमोटिव शेड, साबरमती में एक मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया।

इस मॉक ड्रिल के अंतर्गत सिविल डिफेंस टीम द्वारा एक सुरक्षा जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें शेड के समस्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों को आग लगने की स्थिति में किए जाने वाले उपायों तथा आपातकालीन परिस्थितियों में घायलों को त्वरित सहायता पहुंचाने की प्रक्रिया से अवगत कराया गया।

इस मॉक ड्रिल के दौरान आग पर नियंत्रण पाने का लाइव प्रदर्शन भी किया गया, जिसमें यह बताया गया कि ड्राय केमिकल पाउडर एवं उड$_2$ अग्निशमन यंत्र का उपयोग कर आग पर किस प्रकार नियंत्रण पाया जा सकता है।

इस मॉक ड्रिल में कुल 04 अधिकारी एवं 140 से अधिक कर्मचारी उपस्थित रहे। इस मोकड्रिल का उद्देश्य कर्मचारियों में आपदा प्रबंधन तथा अग्नि सुरक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ाना था।

पश्चिम रेलवे चलाएगी बांद्रा टर्मिनस-ओखा के बीच स्पेशल ट्रेन

पश्चिम रेलवे द्वारा यात्रियों की सुविधा तथा स्वतंत्रता दिवस और जन्माष्टमी के त्योहारी सीजन के दौरान उनकी यात्रा को मांग को पूरा करने के उद्देश्य से बांद्रा टर्मिनस और ओखा स्टेशनों के बीच विशेष किराए पर स्पेशल ट्रेन चलाने का निर्णय लिया गया है। इस ट्रेन का विवरण निम्नानुसार हैः

- ट्रेन संख्या 09077/09078 बांद्रा टर्मिनस - ओखा स्पेशल [4 फेरे]

ट्रेन संख्या 09077 बांद्रा टर्मिनस-ओखा स्पेशल गुरुवार और रविवार को बांद्रा टर्मिनस से 21:20 बजे प्रस्थान करेगी और अगले दिन 05.25 बजे अहमदाबाद एवं 16:45 बजे ओखा पहुँचेगी। यह ट्रेन 14 और 17 अगस्त, 2025 को चलेगी।

इसी प्रकार, ट्रेन संख्या 09078 ओखा-बांद्रा टर्मिनस स्पेशल शनिवार और मंगलवार को ओखा से 08:20 बजे प्रस्थान करेगी और 17.05 बजे अहमदाबाद पहुंचेगी तथा अगले दिन 04:00 बजे बांद्रा टर्मिनस पहुँचेगी। यह ट्रेन 16 और 19 अगस्त, 2025 को चलेगी।

यह ट्रेन दोनों दिशाओं में बोरीवली, पालघर, वापी, वलसाड, सूरत, भरूच, वडोदरा, आणंद, नडियाद, अहमदाबाद, विरमगाम, सुरेंद्रनगर, वांकानेर, राजकोट, जामनगर और द्वारका स्टेशनों पर रुकेगी।

इस ट्रेन में एसी 2-टियर, एसी - 3 टियर, स्लीपर क्लास और द्वितीय श्रेणी के सामान्य डिब्बे होंगे।

ट्रेन संख्या 09077 एवं 09078 की बुकिंग 3 अगस्त, 2025 से पीआरएस काउंटरों और आईआरसीटीसी वेबसाइट पर शुरू होगी। इन ट्रेनों के ठहराव, समय और संरचना के बारे में विस्तृत जानकारी के लिए यात्री कृपया www. enquiry. indianrail. gov.in पर जाकर अवलोकन कर सकते हैं।

मनीला, फिलीपींस की यात्रा पर भारतीय नौसेना के जहाज, दक्षिण पूर्व एशिया में समुद्री सहयोग को मजबूत करेंगे

(जीएनएस)।

दक्षिण पूर्व एशिया में भारतीय नौसेना की चल रही परिचालन तैनाती के हिस्से के रूप में, पूर्वी बेड़े के भारतीय नौसेना जहाज आईएनएस दिल्ली, शक्ति और किल्टन मनीला, फिलीपींस पहुंचे। इन जहाजों की कमान पूर्वी बेड़े के फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग आरएडीएम सुशील मेनन के हाथों में है।

फिलीपींस की नौसेना के कर्मियों ने इन जहाजों का गर्मजोशी से स्वागत किया। इससे भारत और फिलीपींस के बीच मजबूत और बढ़ते समुद्री संबंधों को बल मिला। यह यात्रा हिंद-प्रशांत क्षेत्र में साझेदारी को मजबूत करने की भारतीय नौसेना की प्रतिबद्धता का प्रमाण है।

रियर एडमिरल सुशील मेनन ने वहां पहुंचने पर स्थानीय मीडिया प्रतिनिधियों से बातचीत की और स्थिरता एवं समुद्री सुरक्षा बनाए रखने के प्रति दोनों देशों की साझा प्रतिबद्धता पर प्रकाश डाला। उन्होंने मित्र समुद्री बलों के बीच समझ, विश्वास और सहयोग को बढ़ावा देने में ऐसी तैनाती के महत्व पर जोर दिया।

स्टार्टअप्स और इकोसिस्टम हितधारकों के बीच सहयोग को सुगम बनाता है भास्कर प्लेटफॉर्म

BHASKAR Bharat Startup Knowledge Access Registry
Innovate. Connect. Thrive
A Startup India Initiative

भारत स्टार्टअप नॉलेज एक्सेस रजिस्ट्री (भास्कर) स्टार्टअप्स सहित उद्यमशीलता इकोसिस्टम के बीच सहयोग को सक्षम बनाती है। 30 जून, 2025 तक भास्कर पर 'स्टार्टअप' श्रेणी के अंतर्गत 1,97,932 संस्थाएं पंजीकृत हैं। राज्य/केंद्र शासित प्रदेश वार विवरण अनुलग्नक-क के रूप में दिया गया है। भास्कर वर्तमान में पायलट चरण में है, जिसमें प्रमुख विशेषताओं का परीक्षण किया जा रहा है। इसमें समकक्ष से समकक्ष परस्पर संपर्क, साझेदारी और सहयोगात्मक जुड़ाव, हितधारक श्रेणियों के लिए अनूठी व्यक्तिगत पहचान का निर्माण और स्टार्टअप इंडिया के तहत विभिन्न योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए माइक्रोसाइट्स का समेकन शामिल है। सरकार लघु और सूक्ष्म उद्यमों सहित प्रमुख उपयोगकर्ता हितधारकों की आवश्यकताओं और अनुभवों को समझने के लिए राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में भास्कर के लिए विभिन्न लोकसंपर्क और जागरूकता कार्यक्रम चला रही है।

वडोदरा मंडल पर 'स्वतंत्रता दिवस समारोह-2025' के अंतर्गत स्वच्छता अभियान का शुभारंभ

पश्चिम रेलवे के वडोदरा मंडल पर 'स्वतंत्रता दिवस समारोह-2025' के उपलक्ष्य में दिनांक 1 अगस्त से 15 अगस्त, 2025 तक एक विशेष 'स्वच्छता अभियान' का आयोजन किया जा रहा है। इस पखवाड़े के दौरान, मंडल के विभिन्न स्टेशनों, रेलवे कॉलोनियों और कार्यालयों में स्वच्छता जागरूकता और विशेष सफाई अभियान चलाए जाएंगे। अभियान की शुरूआत वडोदरा मंडल रेल प्रबंधक श्री राजू भडके ने सभी रेल कर्मचारियों और अधिकारियों को स्वच्छता के प्रति सजग रहने की शपथ दिलाकर की। श्री भडके ने रेलकर्मियों से हर वर्ष 100 घंटे यानी प्रति सप्ताह 2 घंटे श्रमदान करने और दूसरों को भी स्वच्छता के प्रति जागरूक करने का आ'ान किया, ताकि पूरे देश को स्वच्छ बनाने में मदद मिल सके।

इस अभियान का मुख्य उद्देश्य मंडल क्षेत्र में स्वच्छता सुनिश्चित करना है, जिसमें विशेष रूप से रेलवे पटरियों और उनके आस-पास के क्षेत्रों से कचरा हटाने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा।

अहमदाबाद मंडल पर स्वतंत्रता दिवस समारोह-2025 के अंतर्गत स्वछता अभियान का शुभारंभ

पश्चिम रेलवे के अहमदाबाद मण्डल पर 'स्वतंत्रता दिवस समारोह'2025 के अंतर्गत 1 अगस्त से 15 अगस्त 2025 तक 'स्वछता अभियान'का आयोजन किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत मंडल क्षेत्र में विभिन्न स्वच्छता जागरूकता और सफाई अभियान चलाए जाएंगे।

अपर मण्डल रेल प्रबंधक श्रीमती मंजू मीणा ने रेल कर्मचारियों एवं अधिकारियों को स्वच्छता के प्रति सजग रहने और हर वर्ष 100 घंटे यानी हर सप्ताह 2 घंटे श्रमदान करने तथा अन्य व्यक्तियों को भी शपथ दिलाकर स्वच्छता के प्रतिजागरूक कर पूरे देश को स्वच्छ बनाने में मदद करने 'की शपथ दिलाई।

इस अभियान के तहत मण्डल पर स्वच्छता सुनिश्चित करने और रेल पटरियों तथा उसके आसपास से, कचरा हटाने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।

भीड़भाड़ की स्थिति का सामना करने वाले 73 प्रमुख स्टेशनों पर एक स्टेशन निदेशक नियुक्त किया जाएगा

(जीएनएस)।

भारतीय रेलवे ने रेलवे स्टेशनों पर यात्रियों की भारी भीड़ को संभालने के लिए निम्नलिखित कार्य योजना बनाई हैः -

73 चिन्हित स्टेशनों पर स्थायी होल्डिंग क्षेत्रों का निमार्णः

2024 के त्यौहारी सीजन के दौरान, स्टेशनों के बाहर होल्डिंग एरिया बनाए गए थे। सूरत, उधना, पटना और नई दिल्ली में ये प्रतीक्षालय बड़ी भीड़ को संभालने में सक्षम थे। यात्रियों को केवल तभी प्रवेश दिया जाता था जब ट्रेन प्लेटफॉर्म पर आती थी।

महाकुंभ के दौरान प्रयाग क्षेत्र के नौ स्टेशनों पर भी ऐसी ही व्यवस्था की गई थी।

इन स्टेशनों के अनुभव के आधार पर, देश भर के 73 स्टेशनों पर, जहाँ समय-समय पर भारी भीड़ होती है, स्टेशनों के बाहर स्थायी प्रतीक्षालय बनाने का निर्णय लिया गया है। प्रतीक्षालय के भीतर भीड़ को नियंत्रित किया जाएगा। यात्रियों को केवल तभी प्लेटफार्म पर जाने की अनुमति होगी जब ट्रेनें प्लेटफार्म पर आएँगी। इससे प्लेटफार्म पर भीड़ कम होगी।

नई दिल्ली, आनंद विहार, वाराणसी, अयोध्या और गाजियाबाद स्टेशनों पर पायलट परियोजनाएं शुरू हो चुकी हैं।

प्रवेश नियंत्रणः

73 चिन्हित स्टेशनों पर पूर्ण प्रवेश नियंत्रण शुरू किया जाएगा।

कन्फर्म आरक्षित टिकट वाले यात्रियों को प्लेटफॉर्म पर सीधे प्रवेश दिया जाएगा।

बिना टिकट वाले या प्रतीक्षा सूची वाले यात्री बाहरी प्रतीक्षालय में प्रतीक्षा करेंगे।

सभी अनाधिकृत प्रवेश बिंदुओं को सील कर दिया जाएगा।

चौड़े फुट-ओवर-ब्रिज (एफओबी):

12 मीटर चौड़े (40 फीट) और 6 मीटर चौड़े (20 फीट) मानक चौड़े फुट- ओवर- ब्रिज एफओबी के दो नए डिजाइन विकसित किए गए हैं। रैंप युक्त ये चौड़े एफओबी महाकुंभ के दौरान भीड़ प्रबंधन में बेहद कारगर रहे। ये नए मानक चौड़े एफओबी सभी स्टेशनों पर लगाए जाएँगे।

कैमरेः

महाकुंभ के दौरान कैमरों ने भीड़ प्रबंधन में बड़े पैमाने पर मदद की। रेलवे स्टेशनों और आसपास के क्षेत्रों में सीसीटीवी कैमरे रेलवे स्टेशनों पर भीड़ की कड़ी निगरानी और प्रबंधन में सहायक होंगे।

युद्ध कक्षः

बड़े स्टेशनों पर वॉर रूम विकसित किए जाएंगे। भीड़भाड़ की स्थिति में सभी विभागों के अधिकारी वॉर रूम में काम करेंगे।

नई पीढ़ी के संचार उपकरणः

सभी अत्यधिक भीड़ वाले स्टेशनों पर वॉकी-टॉकी, उद्घोषणा प्रणाली, कॉलिंग सिस्टम जैसे नवीनतम डिजाइन के डिजिटल संचार उपकरण लगाए जाएंगे।

नये डिजाइन का आईडी कार्डः

सभी कर्मचारियों और सेवाकर्मियों को नए डिजाइन का आईडी कार्ड दिया जाएगा ताकि केवल अधिकृत व्यक्ति ही स्टेशन में प्रवेश कर सकें।

8. कर्मचारियों के लिए नई डिजाइन की वर्दीः

सभी कर्मचारियों को नई डिजाइन की वर्दी दी जाएगी ताकि संकट की स्थिति में उनकी आसानी से पहचान की जा सके।

9. स्टेशन निदेशक पद का उन्नयनः

सभी प्रमुख स्टेशनों पर एक वरिष्ठ अधिकारी स्टेशन निदेशक के रूप में कार्यरत होंगे। अन्य सभी विभाग स्टेशन निदेशक को रिपोर्ट करेंगे।

स्टेशन निदेशक को वित्तीय अधिकार दिए जाएँगे ताकि वे स्टेशन के सुधार के लिए तत्काल निर्णय ले सकें।

10. क्षमता के अनुसार टिकटों की बिक्रीः

स्टेशन निदेशक को स्टेशन और उपलब्ध ट्रेनों की क्षमता के अनुसार टिकटों की बिक्री को नियंत्रित करने का अधिकार होगा।

इसके अलावा, स्टेशनों पर भीड़ को नियंत्रित करने के लिए अन्य हितधारकों के साथ समन्वय में निम्नलिखित कदम उठाए जा रहे हैं :-

भीड़ प्रबंधन सुनिश्चित करने के लिए जीआरपी/ राज्य पुलिस और संबंधित रेलवे विभागों के साथ समन्वय किया जाता है।

राजकीय रेलवे पुलिस (जीआरपी) और रेलवे सुरक्षा बल (आरपीएफ) के कर्मचारियों को भीड़ को सुचारू रूप से नियंत्रित करने और यात्रियों को तत्काल सहायता प्रदान करने के लिए संवेदनशील स्थानों पर तैनात किया जाता है।

भारी भीड़ के दौरान भगदड़ जैसी स्थिति से बचने और यात्रियों को तत्काल सहायता प्रदान करने के लिए भीड़ को सुचारू रूप से नियंत्रित करने हेतु जीआरपी और आरपीएफ कर्मचारियों को फुट-ओवर ब्रिज पर तैनात किया जाता है।

भीड़ के बारे में सूचना एकत्र करने के लिए खुफिया इकाइयों (अपराध खुफिया शाखा (सीआईबी)/ विशेष खुफिया शाखा (एसआईबी)) और सादे कपड़ों में कर्मचारियों को तैनात किया गया है और तदनुसार जीआरपी/ पुलिस को शामिल करते हुए व्यवस्था की गई है।

केंद्रीय रेल, सूचना एवं प्रसारण तथा इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव ने आज राज्यसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में यह जानकारी दी।

मानसिक स्वास्थ्य देखभाल में सुधार के लिए उठाए गए कदम

राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम के जिला मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम घटक को 767 जिलों में कार्यान्वयन के लिए मंजूरी दी गई है

राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम के तृतीयक देखभाल घटक के तहत, मानसिक स्वास्थ्य विशिष्टसताओं में स्नातकोत्तर विभागों में छात्रों का प्रवेश बढ़ाने और तृतीयक स्तर की उपचार सुविधाएं प्रदान करने के लिए 25 उत्कृष्टता केंद्रों को मंजूरी दी गई

36 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों ने 53 टेली मानस प्रकोष्ठ स्थापित किए हैं और टेली मानसिक स्वास्थ्य सेवाएं आरंभ की हैं; हेल्पलाइन नंबर पर 23,82,000 से अधिक कॉलों का समाधान किया गया

(जीएनएस)।

सरकार देश में राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम (एनएमएचपी) का क्रियान्वयन कर रही है। एनएमएचपी के जिला मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम (डीएमएचपी) घटक को 767 जिलों में क्रियान्वयन हेतु स्वीकृत किया गया है, जिसके लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के माध्यम से राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को सहायता प्रदान की जाती है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र (पीएचसी) स्तर पर डीएमएचपी के अंतर्गत उपलब्ध कराई जाने वाली सुविधाओं में बा' रोगी सेवाएं, मूल्यांकन, परामर्श/मनो-सामाजिक युक्तियां, गंभीर मानसिक विकारों से ग्रस्त व्यक्तियों की निरंतर देखभाल और सहायता, दवाइयां, आउटरीच सेवाएं, एम्बुलेंस सेवाएं आदि शामिल हैं। उपरोक्त सेवाओं के अतिरिक्त, जिला स्तर पर 10 बिस्तरों वाली आंतरिक रोगी सुविधा केंद्र का प्रावधान है।

एनएमएचपी के तृतीयक देखभाल घटक के अंतर्गत, मानसिक स्वास्थ्य विशिष्टताओं में स्नातकोत्तर विभागों में छात्रों की संख्या बढ़ाने और तृतीयक स्तर की उपचार सुविधाएं प्रदान करने के लिए 25 उत्कृष्टता केंद्रों को मंजूरी दी गई है। इसके अतिरिक्त, सरकार ने मानसिक स्वास्थ्य विशिष्टताओं में 47 स्नातकोत्तर विभागों को सुदृढ़ करने के लिए 19 सरकारी मेडिकल कॉलेजों/संस्थानों को भी सहायता प्रदान की है।

भारतीय पुनर्वास परिषद (आरसीआई) से प्राप्त जानकारी के अनुसार, वर्तमान में, 69 संस्थानों/विश्वविद्यालयों को नैदानिक मनोविज्ञान में एम.फिल., व्यावसायिक डिप्लोमा, साइकोलॉजी में डॉक्टरेट (डॉक्टर ऑफ साइकोलॉजी) जैसे पाठ्यक्रम संचालित करने के लिए आरसीआई द्वारा अनुमोदित किया गया है और 9 संस्थानों/विश्वविद्यालयों को पुनर्वास मनोविज्ञान में एम.फिल. (पुनर्वास मनोविज्ञान) जैसे पाठ्यक्रम संचालित करने के लिए आरसीआई द्वारा अनुमोदित किया गया है। परिषद ने शैक्षणिक सत्र 2024-25 से नैदानिक मनोविज्ञान में दो और प्रोग्राम, अर्थात बी.एससी. (नैदानिक मनोविज्ञान) और एमए (नैदानिक मनोविज्ञान) भी आरंभ किए हैं।

सरकार डिजिटल अकादमियों के माध्यम से सामान्य स्वास्थ्य देखभाल चिकित्सा और पैरा मेडिकल पेशेवरों की विभिन्न श्रेणियों को ऑनलाइन प्रशिक्षण पाठ्यक्रम प्रदान करके देश के वंचित क्षेत्रों में मानसिक स्वास्थ्य देखभाल सेवाएं प्रदान करने के लिए श्रमबल की उपलब्धता भी बढ़ा रही है।

मानसिक बीमारी के बारे में लोगों में जागरूकता पैदा करने के लिए, समुदाय, स्कूलों, कार्यस्थलों में सामुदायिक भागीदारी के साथ सूचना, शिक्षा और संचार (आईईसी) कार्यकलाप और जागरूकता सृजन कार्यकलाप एनएमएचपी के अभिन्न अंग हैं।

जिला मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम (डीएमएचपी) को राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत देश के 767 जिलों में कार्यान्वित किया जा रहा है, जिसका उद्देश्य मानसिक बीमारियों का पता लगाना, उनका प्रबंधन करना और उनका उपचार करना है। इसके प्रमुख घटकों में स्कूलों और कॉलेजों में परामर्श, कार्यस्थल पर तनाव प्रबंधन, जीवन कौशल प्रशिक्षण, आत्महत्या रोकथाम सेवाएं और जागरूकता पैदा करने तथा मानसिक बीमारी से जुड़े कलंक को दूर करने के लिए सूचना, शिक्षा और संचार (आईईसी) कार्यकलाप शामिल हैं।

सरकार प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा स्तर पर मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करने के लिए भी कदम उठा रही है। सरकार ने 1.77 लाख से अधिक उप-स्वास्थ्य केंद्रों (एसएचसी) और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों (पीएचसी) को आयुष्मान आरोग्य मंदिरों में अपग्रेड किया है। इन आयुष्मान आरोग्य मंदिरों में प्रदान की जाने वाली व्यापक प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा के अंतर्गत सेवाओं के पैकेज में मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं को भी शामिल किया गया है। आयुष्मान भारत के अंतर्गत आयुष्मान आरोग्य मंदिरों में मानसिक, तंत्रिका संबंधी और मादक द्रव्यों के सेवन संबंधी विकारों (एमएनएस) पर विभिन्न संवर्गों के लिए संचालन संबंधी दिशा-निर्देश और प्रशिक्षण नियमावली जारी की गई है।

पश्चिम रेलवे - अहमदाबाद मंडल

ई-निविदा सूचना संख्या: DRM (M) ADI/15/2025-26 दिनांक 29.07.2025

पुन:र्सत्यापन एवं पुन:अंशांकन के विभिन्न अनुबंध कार्य

निविदा संख्या: M233-Repair-SW-VG-GIM-Re

निम्नलिखित कार्यों के लिए पात्र ठेकेदारों से ई-निविदा आमंत्रित की जाती है।

कार्य का नाम: मरम्मत, पेंटिंग, समायोजन, सीलिंग, सील पंचिंग, सफाई, ब्रशिंग, लोडिंग/अनलोडिंग आदि सहित पुनर्व्यवस्था और सी.आई. मास्टर वेट (10 किग्रा, 20 किग्रा, और 50 किग्रा) का 6 वर्षों के लिए पुन:र्सत्यापन/पुन:अंशांकन हेतु अनुंबध कार्य।

कार्य की अनुमानित लागत:₹34,30,257.90/- (रुपये चौंतीस लाख तीस हज़ार दो सौ सत्तावन और नब्बे पैसे मात्र)

बोली सुरक्षा (अर्नेस्ट मनी डिपाजिट): ₹68,600/- (रुपये अड़सठ हज़ार छह सौ मात्र)

निविदा बंद होने और खुलने की तिथि और समय:बंध होने का समय दिनांक 20/08/2025 को 15:00 बजे और खोलने का समय दिनांक 20/08/2025 को 15:30 बजे

वेबसाइट विवरण, नोटिस बोर्ड, स्थान जहां निविदा का पूरा विवरण देखा जा सकता है, तथा निविदा आमंत्रण प्राधिकरण के कार्यालय का पता: मंडल रेल प्रबंधक (यांत्रिक), (पश्चिम रेलवे) द्वितीय तल, मेकेनिकल शाखा, चामुंडा ब्रिज के पास, नरोडा रोड, पोस्ट: सैजपुर बोघा, अहमदाबाद-382345

वेबसाइट: http://www.ireps.gov.in ADI 125

हमें लाइक करें: facebook.com/WesternRly • हमें फॉलो करें: twitter.com/WesternRly

पश्चिम रेल्वे

सामग्री प्रबंधन विभाग

विभिन्न सामग्रियों की आपूर्ति

ई-प्रोक्योरमेंट निविदा सूचना संख्या S/49/2025 दिनांक 29.07.2025

क्र.नं.	आइटम का संक्षिप्त विवरण	मात्रा	टी.ओ.डी.
403	लेटरल बम्प स्टॉप	8658 नंग	22-अगस्त-25
404	लीड एसिड बैटरी क्षमता 8 V, 290 AH.	663 नंग	23-अगस्त-25
405	उन्नत उच्च तन्यता CBC के लिए नकल	15886 नंग	23-अगस्त-25
406	कंप्रेसर प्रकार RR20100CGM, निर्माता मेसर्स ELGI के लिए वार्षिक ओवरहालिंग किट	142 सेट	25-अगस्त-25
407	कैसनब के लिए बोगी सेंटर पिवट टॉप	5957 नंग	25-अगस्त-25
408	स्लैक एडजस्टर प्रकार IRSA-600 पूर्ण	1610 नंग	25-अगस्त-25
409	उन्नत उच्च तन्यता सीबीसी के लिए लॉक	24174 नंग	25-अगस्त-25
410	उन्नत उच्च क्षमता ड्राफ्ट गियर	1386 नंग	25-अगस्त-25
411	मेरोपेनम 1 ग्राम इंजेक्शन	18240 नंग	25-अगस्त-25
412	ग्लार्गिन इंसुलिन 100iu प्रति मिली 3 मिली कार्ट्रिज (प्रति 30 कार्ट्रिज पर एक पेन डिवाइस निःशुल्क प्रदान किया जाएगा)	29908 नंग	25-अगस्त-25
413	ट्रैक्शन ट्रांसफार्मर शीतलन प्रणाली और सहायक उपकरण के साथ पूर्ण	1 नंग	25-अगस्त-25
414	ब्रेन एंडोस्कोपी प्रणाली	2 नंग	25-अगस्त-25
415	स्वचालित ड्रॉपिंग डिवाइस प्रावधान के साथ ईएमयू पैंटोग्राफ के लिए उपयुक्त मेट अलाइव्ड कार्बन स्ट्रिप्स	2363 नंग	28-अगस्त-25
416	शैंक वियर्स प्लेट के साथ कपलर बॉडी	6617 नंग	28-अगस्त-25
417	सीसी पॉली यूरेथेन साइड बियरर पैड असेंबली	2430 नंग	8-सितंबर-25
418	पॉली रिंग (डोनट्स)	104833 नंग	10-सितंबर-25
419	कैसनब 22NLB बोगियों के लिए वेज	10565 नंग	01-अक्टूबर-25

शुद्धिपत्र

कृपया निविदा सूचना संख्या एस-41-2025 दिनांक: 30-06-2025, क्रम संख्या 343 के लिए नियत तिथि को "11.08.2025" पढ़ें।

विस्तृत सूचना ईएमडी, खरीद प्रतिबंध और विस्तृत निविदा शर्तों के संबंध में, कृपया वेबसाइट www.ireps.gov.in और wr.indianrailways.gov.in देखें. 0446

हमें लाईक करें: facebook.com/WesternRly • हमें फोलो करें: X.com/WesternRly

रेलवे स्टेशनों पर प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र परियोजना

रेलवे स्टेशनों पर यात्रियों सहित आम जनता को गुणवत्तापूर्ण और किफायती दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करना इसका लक्ष्य

देश भर में 30 जून 2025 तक कुल 16,912 जन औषधि केंद्र खोले गए, जिनमें से 8,660 जन औषधि केंद्र ग्रामीण क्षेत्रों में खोले गए

(जीएनएस)।

प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र परियोजना स्कीम के अंतर्गत, रेलवे स्टेशनों पर यात्रियों सहित आम जनता को गुणवत्तापूर्ण, किफायती दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए 30 जून, 2025 तक देश भर के रेलवे स्टेशनों पर कुल 106 जन औषधि केंद्र (जेएके) खोले गए हैं।

देश भर में 30 जून, 2025 तक कुल 16,912 कृषि ऋण केंद्र (जेएके) खोले जा चुके हैं, जिनमें से 8,660 ग्रामीण क्षेत्रों में खोले गए हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में पहुंच बढ़ाने के लिए इस योजना के तहत प्राथमिक कृषि ऋण समितियों और अन्य सहकारी समितियों द्वारा जेएके खोलने के लिए सहकारिता मंत्रालय के साथ साझेदारी की गई है।

औसतन, लगभग 10 से 12 लाख लोग प्रतिदिन इन केंद्रों पर आते हैं और ग्रामीण एवं सुदूर क्षेत्रों सहित पूरे देश में किफायती दामों पर गुणवत्तापूर्ण दवाइयां प्राप्त करते हैं। इस योजना के परिणामस्वरूप, पिछले 11 वर्षों में, ग्रामीण एवं सुदूर क्षेत्रों सहित पूरे देश में नागरिकों को ब्रांडेड दवाओं की कीमतों की तुलना में लगभग 38,000 करोड़ रुपए की अनुमानित बचत हुई है।

ग्रामीण और सुदूर क्षेत्रों सहित देश भर के जेएके में सुचारू आपूर्ति और उत्पाद उपलब्धता के लिए, एक संपूर्ण आईटी-सक्षम आपूर्ति श्रृंखला प्रणाली स्थापित की गई है, जिसमें एक केंद्रीय वेयरहाउस, चार क्षेत्रीय वेयरहाउस और 39 वितरक नियुक्त हैं। इसके अतिरिक्त 400 फास्ट-मूविंग जनऔषधि उत्पादों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए उनकी नियमित निगरानी की जाती है। इसके अतिरिक्त, 200 जन औषधि उत्पादों के लिए एक न्यूनतम भंडारण अधिदेश लागू किया गया है, जिसमें स्कीम प्रोडक्ट बास्केट में सबसे अधिक बिकने वाले 100 जनऔषधि उत्पाद और बाजार में तेजी से बिकने वाले 100 जनऔषधि उत्पाद शामिल हैं। भंडारण अधिदेश के तहत, जेएके मालिक अपने द्वारा रखरखाव किए गए उक्त 200 उत्पादों के स्टॉक के आधार पर प्रोत्साहन प्राप्त करने के दावेदार बन जाते हैं।

आज केंद्रीय रसायन एवं उर्वरक राज्य मंत्री श्रीमती अनुप्रिया पटेल ने लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में यह जानकारी दी।

'सभी के लिए आवास' के उद्देश्य : पीएमएवाई-जी के तहत आवासों का निर्माण

(जीएनएस)।

ग्रामीण विकास मंत्रालय ग्रामीण क्षेत्रों में "सभी के लिए आवास" के उद्देश्य को हासिल करने के लिए 1 अप्रैल 2016 से प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (पीएमएवाई-जी) का कार्यान्वयन कर रहा है, जिसका उद्देश्य पात्र ग्रामीण परिवारों को बुनियादी सुविधाओं के साथ पक्के मकानों के निर्माण के लिए सहायता प्रदान करना है।

पीएमएवाई-जी के तहत, प्रारंभिक लक्ष्य वित्तीय वर्ष 2016-17 से 2023-24 तक 2.95 करोड़ मकानों के निर्माण के लिए सहायता प्रदान करना था। भारत सरकार ने 2 करोड़ अतिरिक्त मकानों के निर्माण हेतु सहायता प्रदान करने के लिए वित्तीय वर्ष 2024-25 से 2028-29 तक इस योजना के कार्यान्वयन को मंजूरी दे दी है। पीएमएवाई-जी के तहत लाभार्थियों की पहचान सामाजिक-आर्थिक जाति जनगणना (एसईसीसी) 2011 डेटाबेस और अंतिम आवास+ सर्वेक्षण सूची के तहत आवास अभाव मानदंडों के आधार पर की जाती है।

भारत सरकार ने अप्रैल, 2024 से मार्च, 2029 तक बुनियादी सुविधाओं के साथ 2 करोड़ पक्के मकानों की समग्र सीमा के भीतर सहायता प्रदान करके आवास+ (2018) सूची (अद्यतन के बाद) को पूरा करने और एसईसीसी 2011 स्थायी प्रतीक्षा सूची

(पीडब्ल्यूएल) में शेष पात्र परिवारों को रखने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना- ग्रामीण (पीएमएवाई-जी) को जारी रखने की मंजूरी दे दी है।

पीएमएवाई-जी के तहत, 29 जुलाई 2025 तक, मंत्रालय ने राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों को 4.12 करोड़ मकानों का संचयी लक्ष्य (चरण क + चरण क्क) आवंटित किया है, जिसकी तुलना में राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों ने 3.84 करोड़ लाभार्थियों को मंजूरी दी है और 2.81 करोड़ मकान पहले ही बनकर तैयार हो चुके हैं।

लाभार्थियों को किश्तें जारी करना, निर्माण के पूर्व-निर्धारित चरण के पूरा होने और उस चरण की समय एवं दिनांक के साथ जियो-टैग की गई तस्वीर को "आवासऐप" के माध्यम से "आवाससॉफ्ट" पर अपलोड करने पर निर्भर करता है। पीएमएवाई-जी के तहत, मकानों के निर्माण के प्रत्येक चरण में समय और दिनांक के साथ जियो-टैग की गई तस्वीरें अपलोड करना अनिवार्य है, जिसमें मकानों की मंजूरी से पहले 'मौजूदा स्थल' और 'प्रस्तावित स्थल' की जियो-टैगिंग भी शामिल है। मंत्रालय का "आवासऐप" मोबाइल एप्लिकेशन इसकी सुविधा प्रदान करता है। 29 जुलाई, 2025 तक, प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (पीएमएवाई-जी) योजना के तहत लाभार्थियों को मकान स्वीकृत करने से पहले 3.84 करोड़ मकानों की साइटों की जियो-टैगिग की जा चुकी है।

यह जानकारी ग्रामीण विकास राज्य मंत्री श्री डॉ. चंद्रशेखर पेम्मासानी ने आज राज्यसभा में एक लिखित उत्तर में दी।

लीवर सिरोसिस के उपचार में एक नया दृष्टिकोण

(जीएनएस)।

भारतीय वैज्ञानिकों की एक टीम ने वीईजीएफ-सी नामक एक शक्तिशाली प्रोटीन से भरे नैनोकैरियर का उपयोग करके लीवर और आंत में लसीका वाहिकाओं की जल निकासी क्षमता में सुधार करने का एक तरीका खोजा होगा, जो सिरोसिस के मामले में विफल हो जाती है।

पुरानी लीवर की बीमारी हल्की बीमारी से लेकर फाइब्रोसिस से सिरोसिस तक बढ़ सकती है। उन्नत सिरोसिस वाले मरीजों में अक्सर पेट में तरल पदार्थ जमा होने (एसाइटिस) जैसी जटिलताओं के साथ डीकंपनसेशन विकसित होता है।

सिरोसिस के साथ लीवर और आंत दोनों में रक्त और लसीका वाहिकाओं का विकृति होती है। लसीका वाहिकाएं रक्त वाहिकाओं के समानांतर चलती हैं, जो अतिरिक्त अंतरालीय द्रव, प्रोटीन और प्रतिरक्षा कोशिकाओं को निकालती हैं और उन्हें वापस शिरा से बहने वाले रक्त में पहुंचाती हैं। सिरोसिस में आंतों की मेसेंटेरिक लसीका वाहिकाएं (एमएलवीएस) बढ़ जाती हैं लेकिन फैली हुई और निष्क्रिय रहती हैं।

लीवर कंजेशन और पोर्टल वैस्कुलर सिस्टम के दबाव में वृद्धि के कारण, सिरोसिस में पेट के लसीका का उत्पादन 30 गुना बढ़ जाता है। लिम्फ के बढ़े हुए निर्माण के साथ-साथ मौजूदा एमएलवी की कम लिम्फ

प्रवाह और जल निकासी क्षमता, उन्नत सिरोसिस वाले मरीजों में पेट में तरल पदार्थ जमा होने का कारण बनती है। आज तक, डीकंपनसेटेड सिरोसिस वाले मरीजों के लिए कोई प्रभावी उपचार नहीं है।

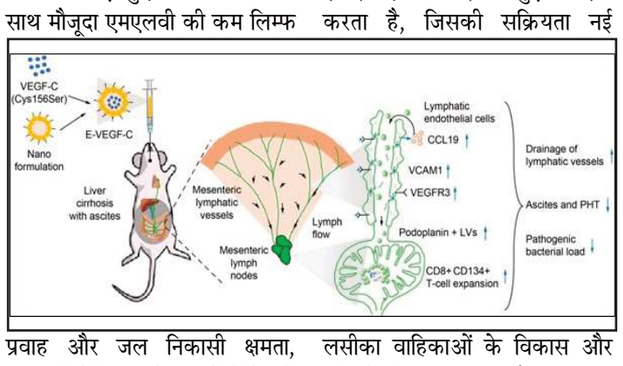

वैस्कुलर एंडोथेलियल ग्रोथ फैक्टर-सी (वीईजीएफ-सी) एक प्रमुख प्रो-लिम्फेंजियोजेनिक कारक है जो लिम्फेंजियोजेनेसिस या नई लसीका वाहिका वृद्धि को सक्रिय करता है। यह एक कोशिका झिल्ली टायरोसिन किनसे रिसेप्टर, वैस्कुलर एंडोथेलियल ग्रोथ फैक्टर रिसेप्टर-3 (वीईजीएफआर-3) से जुड़कर ऐसा करता है, जिसकी सक्रियता नई लसीका वाहिकाओं के विकास और वृद्धि के लिए आवश्यक है।

रिकॉम्बिनेंट वीईजीएफ-सी पहले नई लसीका वाहिकाओं के विकास को प्रोत्साहित करने, लसीका जल निकासी और प्रतिरक्षा प्रतिक्रियाओं में सुधार करने में प्रभावी साबित हुआ है।

चित्रः यह इलस्ट्रेशन इस बात को रेखांकित करता है कि वैस्कुलर एंडोथेलियल ग्रोथ फैक्टर-सी (वीईजीएफ-सी) एक प्रमुख प्रो-लिम्फेंजियोजेनिक कारक है, जो बेहतर मेसेंटेरिक लसीका जल निकासी और आंत की प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया प्रदान करता है व इसे सिरोसिस के इलाज के लिए एक आशाजनक विकल्प बनाता है

लीवर और पित्त विज्ञान संस्थान (आईएलबीएस) नई दिल्ली और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्युटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च (एनआईपीईआर) गुवाहाटी के वैज्ञानिकों की एक टीम ने मिलकर, आंत की लसीका शिथिलता को सुधारने और लसीका जल निकासी को बेहतर बनाने में वीईजीएफ-सी की चिकित्सीय प्रभावकारिता की जांच करने का बीड़ा उठाया। उन्होंने अध्ययन किया कि क्या वीईजीएफ-सी अंतिम चरण के लिवर सिरोसिस में एसाइटिस को कम करने और सूजन को कम करने में मदद कर सकता है।

वीईजीएफ-सी की हाइड्रोफिलिसिटी, कम अर्ध-जीवन और प्रणालीगत दुष्प्रभावों के कारण, एनआईपीईआर गुवाहाटी से डॉ. शुभम बनर्जी की टीम ने पहले वीईजीएफ-सी से भरे रिवर्स मिसेल-आधारित नैनोकैरियर्स के विकास पर ध्यान केंद्रित किया, जो विशेष रूप से वीईजीएफआर-3 होमोडिमर्स से जुड़ते हैं।

इसके बाद, डॉ. सवनीत कौर के नेतृत्व में आईएलबीएस की टीम ने उन्नत सिरोसिस और पोर्टल उच्च रक्तचाप के पशु मॉडल में विकसित वीईजीएफ-सी नैनोकैरियर्स का बड़े पैमाने पर परीक्षण किया। विकसित अणु को मौखिक मार्ग से दिया गया ताकि पशु मॉडल में इसकी आंत की लसीका वाहिका में अवशोषण सुनिश्चित हो सके। टीम ने दिखाया कि वीईजीएफ-सी नैनोकैरियर्स ने मेसेंटेरिक लसीका जल निकासी को काफी बढ़ा दिया, जिससे एसाइटिस कम हुआ। महत्वपूर्ण बात यह है कि इस उपचार से पोर्टल दबाव में भी कमी आई, मेसेंटेरिक लिम्फ नोड्स में साइटोटॉक्सिक टी-सेल प्रतिरक्षा में सुधार हुआ और स्थानीय और प्रणालीगत जीवाणु भार कम हुआ।

हिमालयी बादलों में जहरीली धातुएं स्वास्थ्य के लिए खतरनाक

(जीएनएस)।

हिमालय की ऊंचाइयों में, जहां बादल बर्फ से ढकी चोटियों के ऊपर तैरते रहते हैं, वहां हवा के साथ एक खतरनाक प्रदूषण फैल रहा है। एक नए वैज्ञानिक अध्ययन से पता चला है कि बादल, जिन्हें पहले सबसे शुद्ध पेयजल का स्रोत माना जाता था, निचले प्रदूषित इलाकों से जहरीली धातुओं को धरती के सबसे ऊंचे और नाजुक पारिस्थितिकी तंत्रों तक चुपचाप पहुंचा रहे हैं।

इन निष्कर्षों ने से केवल स्वच्छ पर्वतीय वर्षा का भ्रम समाप्त हो रहा है बल्कि मानव स्वास्थ्य के लिए भी यह खतरे का अलार्म भी बजा रहा है जिसमें कैंसर से लेकर विकास संबंधी विकारों के संभावित खतरे मौजूद हैं।

बादलों में धातुओं का होना चिंताजनक है क्योंकि महाद्वीपीय लंबी दूरी के परिवहन द्वारा मानव स्वास्थ्य पर इसका व्यापक प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। हालांकि, निम्न-स्तरीय बादलों, विशेष रूप से भारत में देर से आने वाले गर्मियों एवं शुरूआती मानसूनी बादलों में धातु सम्मिश्रण की जानकारी की कमी है।

बोस इंस्टीट्यूट, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग (डीएसटी) के अंतर्गत आने वाला एक स्वायत्त संस्थान, ने पश्चिमी घाट एवं पूर्वी हिमालय पर मानसून की शुरूआत में गैर-वषाकारी बादलों में विषाक्त धातुओं की उपस्थिति देखी। उन्होंने यह भी पाया कि पूर्वी हिमालयों के ऊपर के बादलों में 40-60% अधिक विषाक्त धातुओं जैसे कैडमियम, तांबा और जिंक का स्तर उच्च होने के कारण 1.5 गुना ज्यादा प्रदूषण स्तर था, जो भारी यातायात एवं औद्योगिक उत्सर्जनों से उत्पन्न होतें है, जो कैंसरजन्य रोगों का कराण बनते हैं और उच्च स्वास्थ्य जोखिम प्रस्तुत करते हैं।

डॉ. सनत कुमार दास, एसोसिएट प्रोफेसर, बोस संस्थान के नेतृत्व में वायुमंडलीय अनुसंधान दल ने सांस लेने, निगलने एवं त्वचा द्वारा अवशोषण के माध्यम से कैंसरजन्य और गैर-कैंसरजन्य रोगों के जोखिम का आकलन किया। उन्होंने इन धातुओं के संभावित स्रोतों की पहचान करने के लिए सांख्यिकीय मॉडलों का उपयोग करते हुए एक विस्तृत अध्ययन किया।

वर्तमान अवलोकन एवं सिमुलेशन के परिणामों से पता चला कि भारतीय बच्चों में वयस्कों की तुलना में ऐसी विषाक्त धातुओं से 30% ज्यादा खतरा है। पूर्वी हिमालय के ऊपर विषाक्त धातुओं की उच्च सांद्रता वाले प्रदूषित बादलों का सांस के माध्यम से अंतर्ग्रहण गैर-कैंसरजन्य रोगों के लिए सबसे संभावित मार्ग है।

इसके अलावा अध्ययन से यह भी पता चला कि बादलों में घुले क्रोमियम के सांस द्वारा शरीर में प्रवेश करने से कैंसरजन्य रोगों का खतरा बढ़ गया है। अध्ययन के अनुसार, पूर्वी हिमालय में वाहनों एवं औद्योगिक उत्सर्जन से निकलने वाले कार्बन डाइऑक्साइड, क्रोमियम, तांबा और जस्ता जैसे विषैले धातुओं से युक्त उच्च प्रदूषित बादल पाए जाते हैं। ऐसे प्रदूषित बादलों का सांस के माध्यम से शरीर में प्रवेश करना भारत में कैंसरजन्य एवं गैर-कैंसरजन्य रोगों के संभावित कारण है।

बादल परिवहन माध्यम के रूप में कार्य करते हैं, मिश्रित भारी धातुओं को अपने साथ ले जाते हैं,

न्यायपालिका के लिए बुनियादी ढांचे का विकास

भारतीय न्यायपालिका के सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी) विकास के लिए ई-कोर्ट परियोजना को 2007 से एकीकृत मिशन मोड परियोजना के रूप में क्रियान्वित किया जा रहा है

ई-फाइलिंग प्रणाली (संस्करण 3.0) को उन्नत सुविधाओं के साथ शुरू किया गया है, जिससे वकील मामलों से संबंधित दस्तावेजों को किसी भी स्थान से अपलोड कर सकते हैं

(जीएनएस)।

न्याय विभाग वर्ष 1993-94 से न्यायपालिका के लिए ढांचागत बुनियादी सुविधाओं के विकास हेतु केंद्र प्रायोजित योजना (सीएसएस) का क्रियान्वयन कर रहा है ताकि राज्य सरकारों के संसाधनों को एक निर्धारित निधि साझाकरण रूप में बढ़ाया जा सके। इस योजना के अंतर्गत पांच घटक हैं: न्यायालय कक्ष, आवासीय क्वार्टर, वकीलों के कक्ष, डिजिटल कंप्यूटर कक्ष और शौचालय परिसर।

योजना के आरंभ से अब तक इसके अंतर्गत 12,101.89 करोड़ रुपये जारी किए जा चुके हैं, जिनमें से 8,657.59 करोड़ रुपये (71.54 प्रतिशत) वर्ष 2014-15 के बाद से जारी किए गए हैं। वर्ष 2014 में 15,818 न्यायालय कक्षों और 10,211 आवासीय इकाइयों से बढ़कर अब उपलब्ध न्यायालय कक्षों और आवासीय इकाइयों की संख्या क्रमशः 22372 (41.43 प्रतिशत वृद्धि) और 19,851 (94.40 प्रतिशत वृद्धि) हो गई है।

इस योजना के अंतर्गत महाराष्ट्र को 1,099.83 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की गई है। इस राशि में से वर्ष 2014-15 से अब तक 700.17 करोड़ रुपये (63.67 प्रतिशत) जारी किए जा चुके हैं। चालू वित्त वर्ष के लिए महाराष्ट्र राज्य के लिए 28.06 करोड़ रुपये निर्धारित किए गए हैं। वर्तमान में महाराष्ट्र राज्य में 2,503 न्यायालय भवन और 2,202 आवासीय इकाइयां उपलब्ध हैं। इसके अतिरिक्त 560 न्यायालय भवन और 144 आवासीय इकाइयां निमार्णाधीन हैं।

राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस योजना के एक भाग के रूप में, भारतीय न्यायपालिका के सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी) विकास हेतु ई-न्यायालय परियोजना को 2007 से एक एकीकृत मिशन मोड परियोजना के रूप में क्रियान्वित किया जा रहा है। ई-न्यायालय परियोजना के तीसरे चरण (2023 से 2027 की अवधि के लिए) को सितंबर 2023 में 7,210 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ अनुमोदित किया गया था। तीसरे चरण के अंतर्गत न्यायालय प्रबंधन प्रक्रियाओं में सुधार और वकीलों, मुकदमा करने वालों और न्यायाधीशों सहित विभिन्न हितधारकों के लिए सेवाओं के डिजिटलीकरण हेतु कई कदम उठाए गए हैं।

ई-कोर्ट परियोजना के तीसरे चरण का एक घटक केस रिकॉर्ड की स्कैनिंग, डिजिटलीकरण और डिजिटल संरक्षण है, जिसके लिए 2038.40 करोड़ रुपये की राशि निर्धारित की गई है। सर्वोच्च न्यायालय की ई-कमेटी द्वारा प्रदान की गई जानकारी के अनुसार, 30 जून, 2025 तक उच्च न्यायालयों में 213.29 करोड़ पृष्ठों और जिला न्यायालयों में 307.89 करोड़ पृष्ठों का डिजिटलीकरण किया जा चुका है। उच्च न्यायालयों और जिला न्यायालयों के न्यायिक रिकॉर्ड के संरक्षण के लिए सॉफ्टवेयर विकसित किया गया है। इसके अतिरिक्त अदालतों को कागज रहित तरीके से काम करने में सहायता के लिए डिजिटल कोर्ट्स 2.1 सॉफ्टवेयर विकसित किया गया है।

ई-फाइलिंग प्रणाली (संस्करण 3.0) को उन्नत सुविधाओं के साथ शुरू किया गया है ताकि वकील किसी भी स्थान से मामलों से संबंधित दस्तावेजों को अपलोड कर सकें। इसके अतिरिक्त शुल्क आदि के सरल हस्तांतरण के लिए ई-भुगतान प्रणाली शुरू की गई है। राष्ट्रीय सेवा और इलेक्ट्रॉनिक प्रक्रियाओं की ट्रैकिंग (एनएसटीईपी) प्रौद्योगिकी-सक्षम प्रक्रिया तामील और समन जारी करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इसके अलावा, बेंच, केस प्रकार, केस संख्या, वर्ष, याचिकाकर्ता/प्रतिवादी का नाम आदि जैसी सुविधाओं के साथ एक जजमेंट सर्च पोर्टल शुरू किया गया है। यह निशुल्क सुविधा सबके लिए उपलब्ध है। नागरिक-केंद्रित सेवाओं तक आसान और परेशानी मुक्त पहुंच की सुविधा के लिए, देश भर में 1814 ई-सेवा केंद्र (सुविधा केंद्र) स्थापित किए गए हैं। इसके अतिरिक्त, यातायात संबंधी अपराधों की सुनवाई के लिए 21 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में 29 वर्चुअल कोर्ट कार्यरत हैं।

यह जानकारी विधि एवं न्याय मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री श्री अर्जुन राम मेघवाल ने आज लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में दी।

सुश्री सोनाली मिश्रा, आईपीएस, ने रेलवे सुरक्षा बल के महानिदेशक का पदभार ग्रहण किया

(जीएनएस)।

रेलवे सुरक्षा बल (आरपीएफ) ने मध्य प्रदेश कैडर की 1993 बैच की आईपीएस सुश्री सोनाली मिश्रा का आरपीएफ के नए महानिदेशक के रूप में स्वागत किया है, जो बल की 143 साल की यात्रा में पहला ऐतिहासिक कदम है।

कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने 31 अक्टूबर, 2026 को उनकी सेवानिवृत्ति तक डीजी/आरपीएफ के पद पर उनकी नियुक्ति को मंजूरी दे दी है।

प्रमुख पुलिस भूमिकाओं में अपनी व्यावसायिकता, समर्पण और नेतृत्व क्षमता के लिए जानी जाने वाली सुश्री मिश्रा इस पद पर तीन दशकों से अधिक की विशिष्ट सेवा का अनुभव रखती हैं। इस कार्यभार से पहले, उन्होंने अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (चयन/भर्ती) के रूप में कार्य किया, साथ ही पुलिस प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान, भोपाल में एडीजी और मध्य प्रदेश पुलिस अकादमी, भोपाल में निदेशक का अतिरिक्त प्रभार भी संभाला। उन्होंने सीबीआई और

बीएसएफ में भी सेवा की है और कोसोवो में संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन में सेवा देने का अंतरराष्ट्रीय अनुभव भी प्राप्त है।

उत्कृष्टता और व्यावसायिकता के प्रति उनकी प्रतिबद्धता के लिए उन्हें विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पुलिस पदक और सराहनीय सेवा के लिए पुलिस पदक सहित कई प्रतिष्ठित पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है।

दुनिया के सबसे बड़े रेल नेटवर्कों में से एक, रेलवे संपत्ति की सुरक्षा, यात्री सुरक्षा और अपराध रोकथाम के लिए ज़िम्मेदार रेलवे सुरक्षा बल को उनके दूरदर्शी और समावेशी नेतृत्व का लाभ मिलेगा। राज्य और केन्द्रीय पुलिस संगठनों में उनके व्यापक अनुभव से बल के आधुनिकीकरण, क्षमता निर्माण और सामुदायिक सहभागिता को नई गति मिलने की उम्मीद है।

विशेष रूप से, उनका ध्यान अत्याधुनिक तकनीक का लाभ उठाने में आरपीएफ की पहल को मजबूत करने और मानव तस्करी तथा असुरक्षित यात्रियों के विरुद्ध अपराधों जैसे संगठित अपराधों को रोकने में इसकी भूमिका को बढ़ाने पर होगा।

कार्यभार ग्रहण करते हुए, सुश्री मिश्रा ने सेवा के अवसर के लिए आभार व्यक्त किया और सतर्कता, साहस और सेवा के मूल्यों को बनाए रखने के लिए अपनी प्रतिबद्धता दोहराई, जो आरपीएफ के आदर्श वाक्य "यशो लाभस्व" को परिभाषित करते हैं।

बल अपने नए प्रमुख का गर्व से स्वागत करता है और उनके नेतृत्व में नई उपलब्धियाँ हासिल करने की आशा करता है।

कृषि क्षेत्र में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का उपयोग

(जीएनएस)।

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय विभिन्न गतिविधियों के लिए स्पेस टेक्नॉलजी का उपयोग कर रहा है, जिसमें फसल (ऋअरअछ) प्रोजेक्ट (अंतरिक्ष, कृषि-मौसम विज्ञान और भूमि आधारित अवलोकनों का उपयोग करके कृषि उत्पादन का पूर्वानुमान), सूखा निगरानी और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई) को तकनीकी सहायता प्रदान करना शामिल है।

फसल प्रोजेक्ट के अंतर्गत प्रमुख फसलों अर्थात चावल, गेहूं, अरहर, रेपसीड और सरसों, रबी, ज्वार, कपास, जूट, गन्ना, सोयाबीन, मसूर और चना के लिए फसल उत्पादन का पूर्वानुमान लगाया जा रहा है।

सूखे की निगरानी के लिए, विभाग ने एस.ए.सी. (इसरो), अहमदाबाद के सहयोग से एक जियोपोर्टल विकसित किया है। इस पोर्टल पर वर्षा, मृदा नमी, रिमोट सेंसिंग के

आधार पर फसल की स्थिति, जल भंडारण आदि से संबंधित विभिन्न सूखा संकेतकों का डेटा उपलब्ध है।

पीएमएफबीवाई के अंतर्गत विभिन्न परिचालन अनुप्रयोगों जैसे फसल कटाई प्रयोगों (सीसीई) के लिए स्मार्ट सैंपलिंग, उपज अनुमान और विवाद का समाधान (क्षेत्र और उपज) के लिए स्पेस टेक्नॉलजी का भी उपयोग किया जा रहा है।

इसके अतिरिक्त, सरकार ने कृषि निर्णय सहायता प्रणाली (कृषि-डी.एस.एस.) विकसित की है, जो एक क्लाउड-आधारित भू-स्थानिक प्लेटफॉर्म है जो कृषि क्षेत्र के विभिन्न स्टेकहोल्डर्स को सशक्त बनाने के लिए स्पेस टेक्नॉलजी का लाभ उठाता है। कृषि-डीएसएस प्लेटफॉर्म विभिन्न प्रकार के डेटासेट होस्ट करता है, जिनमें मौसम संबंधी आँकड़े, सैटेलाइट इमेज, सॉइल लेयर, जल संबंधी आँकड़े और क्षेत्र की जानकारी शामिल है। कृषि-डी.एस.एस. कृषि प्रबंधन और निर्णय लेने में सहायता के लिए विभिन्न मॉड्यूल/एल्गोरिदम प्रदान करता है।

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने वर्ष 2019-23 के बीच विभिन्न सरकारी और निजी एजेंसियों की मदद से उपज अनुमान के लिए स्पेस टेक्नॉलजी का उपयोग करते हुए पायलट अध्ययन किए हैं। इस अध्ययन में ग्राम पंचायत (जी.पी.) स्तर पर उपज अनुमान लगाने के लिए विभिन्न तकनीकों जैसे उपग्रह, मानवरहित हवाई वाहन (यू.ए.वी.), सिमुलेशन मॉडल और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस/मशीन लर्निंग (ए.आई./एम.एल.) तकनीकों का उपयोग किया गया। पायलट अध्ययनों के निष्कर्षों के आधार पर, किसानों को समय पर और पारदर्शी दावा निपटान के लिए पीएमएफबीवाई की येस-टेक (यील्ड एस्टीमेशन सिस्टम यूजिंग टेक्नॉलजी) पहल के तहत खरीफ 2023 से धान और गेहूं की फसल और खरीफ 2024 से सोयाबीन की फसल के लिए स्पेस टेक्नॉलजी बेस्ड जी.पी. लेवल उपज अनुमान प्राप्त किया गया है।

यह जानकारी कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री श्री रामनाथ ठाकुर ने आज राज्यसभा में एक लिखित उत्तर में दी।

क्रॉपिक के माध्यम से फसल की हानि के आकलन को स्वचालित करना

(जीएनएस)।

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत प्रौद्योगिकी पहलों में से एक, क्रॉपिक (फसलों के वास्तविक समय अवलोकन और फोटो का संग्रह), फसल के खेतों की तस्वीरें एकत्र करने, फसलों के स्वास्थ्य का पता लगाने और आपदाओं से होने वाले नुकसान की पहचान करने हेतु एक डिजिटल एप्लिकेशन है। क्रॉपिक ऐप का उद्देश्य स्मार्टफोन के माध्यम से किसानों और क्षेत्र समन्वयकों से जियोटैग्ड क्राउडसोर्स्ड तस्वीरें एकत्र करना है। टाइम-सीरीज जियोटैग्ड तस्वीरों का उद्देश्य बीमित फसलों के फसल सत्यापन और स्थानीय आपदाओं की स्थिति में फसल क्षति

का आकलन करना है।

क्रॉपिक की परिकल्पना फसल बीमा स्टेकहोल्डर्स को फसलों की निगरानी और प्रबंधन के लिए एक पारदर्शी, वास्तविक समय, साक्ष्य-आधारित प्रणाली प्रदान करके सशक्त बनाने, फसल बीमा और आपदा प्रतिक्रिया की प्रभावशीलता को सुदृढ़ करने और डेटा-आधारित नीतिगत निर्णय सुनिश्चित करने के लिए की गई है। तथापि, क्रॉपिक डेटा पर सार्वजनिक डैशबोर्ड उपलब्ध कराने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

इसके अतिरिक्त, एक कृषि रक्षक पोर्टल और हेल्पलाइन (ङ्फ्ढल) शुरू की गई है, जिसका अखिल भारतीय टोल-फ्री नंबर 14447 है और इसे बीमा कंपनियों के डेटाबेस से जोड़ा गया है, जहाँ किसान अपनी शिकायतें/मुद्दे दर्ज करा सकते हैं। इन शिकायतों के समाधान के लिए समय-सीमा भी तय की गई है।

यह जानकारी कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री श्री रामनाथ ठाकुर ने आज राज्यसभा में एक लिखित उत्तर में दी।